नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 165
दि. 20.03.2026,
शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

मिडिल ईस्ट में 'ऊर्जा युद्ध' की आग: गैस फील्ड से रिफाइनरियों तक हमलों ने बढ़ाया वैश्विक संकट

मध्य-पूर्व एक बार फिर भीषण संघर्ष की चपेट में है, लेकिन इस बार यह जंग केवल सीमाओं, सेनाओं और हथियारों तक सीमित नहीं रही, बल्कि दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की रीढ़ माने जाने वाले तेल और गैस ठिकानों तक पहुंच चुकी है। Middle East में जारी इस टकराव ने वैश्विक चिंता को चरम पर पहुंचा दिया है, क्योंकि इसका सीधा असर अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार, अर्थव्यवस्था और कूटनीतिक संतुलन पर पड़ सकता है।

घटनाक्रम ने नया मोड़ तब लिया जब 18 मार्च को Israel ने Iran के सबसे महत्वपूर्ण गैस क्षेत्र South Pars Gas Field पर हमला कर दिया। यह वही गैस फील्ड है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार माना जाता है और जो ईरान तथा Qatar के बीच साझा है। इस हमले ने न केवल क्षेत्रीय संघर्ष को और भड़का दिया, बल्कि इसे सीधे तौर पर वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के संकट में बदल दिया।

बताया जाता है कि यह गैस क्षेत्र ईरान की लगभग 70 प्रतिशत घरेलू गैस आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है। ऐसे में इस पर हमला होना ईरान के लिए एक गहरी आर्थिक और रणनीतिक चोट के रूप में देखा जा रहा है। इस हमले के बाद ईरान ने आक्रामक रुख अपनाते हुए जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी और पड़ोसी खाड़ी देशों के ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाया।

ईरान की जवाबी कार्रवाई का सबसे बड़ा असर Kuwait, Saudi Arabia, United Arab Emirates और कतर जैसे देशों पर देखने को मिला। कुवैत की मीना अब्दुल्लाह रिफाइनरी पर मिसाइल हमले के बाद वहां आग लग गई, जिससे उत्पादन पर असर पड़ा। इसी तरह सऊदी अरब की दिग्गज तेल कंपनी Saudi Aramco की SAMREF रिफाइनरी को भी निशाना बनाया गया, जिसकी उत्पादन क्षमता लगभग 7.3 लाख बैरल प्रतिदिन बताई जाती है। इस हमले ने वैश्विक तेल आपूर्ति को लेकर चिंताओं को और गहरा कर दिया।

कतर के Ras Laffan Industrial City में स्थित दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी केंद्र पर भी ईरान के हमलों का असर पड़ा। कतर वैश्विक स्तर पर एलएनजी का एक बड़ा निर्यातक है, ऐसे में यहां किसी भी प्रकार की बाधा का सीधा असर यूरोप, एशिया और अन्य बाजारों पर

पड़ सकता है। ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह संघर्ष लंबा खिंचता है, तो गैस की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है और आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो सकती है।

United Arab Emirates के अबू धाबी स्थित Ruwais Refinery पर भी ड्रोन हमले किए गए, जिसके बाद एहतियात के तौर पर वहां उत्पादन रोक दिया गया। हालांकि, वहां संचालित कंपनी ADNOC ने बड़े नुकसान की पुष्टि नहीं की है, लेकिन सुरक्षा कारणों से गतिविधियां सीमित कर दी गईं। इसी तरह सऊदी अरब के रास तनुरा रिफाइनरी पर भी हमलों के कारण आग लगने की खबरें सामने आईं, हालांकि बाद में वहां आंशिक रूप से कामकाज बहाल कर दिया गया।

इन हमलों के बीच राहत की बात यह रही कि अब तक किसी बड़े पैमाने पर जनहानि की खबर नहीं आई है, लेकिन ऊर्जा ढांचे को हुए नुकसान ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। इस संघर्ष का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि अब यह युद्ध पारंपरिक सैन्य टकराव से निकलकर आर्थिक और ऊर्जा संसाधनों की जंग बन चुका है।

इस पूरे घटनाक्रम पर Donald Trump की प्रतिक्रिया भी काफी तीखी रही। उन्होंने स्पष्ट किया कि साउथ पार्स पर हमला Israel ने अपने स्तर पर किया था और इसमें अमेरिका या कतर की कोई भूमिका नहीं थी। साथ ही उन्होंने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उसने दोबारा कतर के एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया, तो अमेरिका स्वयं साउथ पार्स गैस फील्ड को पूरी तरह तबाह कर सकता है। यह बयान इस बात का संकेत है कि यह संघर्ष किसी भी समय और अधिक व्यापक रूप ले सकता है।

दूसरी ओर, France के राष्ट्रपति Emmanuel Macron ने भी स्थिति को लेकर चिंता जताई और कतर के साथ बातचीत कर संयम बरतने की अपील की। हालांकि ईरान ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने उसके खिलाफ हुए हमलों की पर्याप्त निंदा नहीं की।

इस बढ़ते तनाव के बीच करीब एक दर्जन अरब और इस्लामिक देशों—जिनमें Saudi Arabia, Egypt, Pakistan और Turkey शामिल हैं—ने संयुक्त बयान जारी कर ईरान से हमले रोकने और अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करने की अपील की है। यह कूटनीतिक प्रयास इस बात का संकेत है कि क्षेत्रीय देश इस संघर्ष को और बढ़ने से रोकना चाहते हैं।

वर्तमान स्थिति यह दर्शाती है कि यह टकराव केवल क्षेत्रीय नहीं रहा, बल्कि वैश्विक प्रभाव वाला संकट बन चुका है। यदि ऊर्जा ठिकानों पर हमले जारी रहते हैं, तो इसका असर केवल खाड़ी देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया में ईंधन की कीमतों, आपूर्ति और आर्थिक स्थिरता पर गहरा प्रभाव पड़ेगा।

केरल में एनडीए को झटका, 'ट्वेंटी20' की चुनावी रणनीति पर उठे सवाल

केरल की सियासत उस समय अचानक सुर्खियों में आ गई जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सहयोगी पार्टी 'ट्वेंटी20' को एक ऐसा झटका लगा, जिसने उसकी चुनावी तैयारियों पर ही सवाल खड़े कर दिए। चुनावी प्रक्रिया के बीच दो प्रमुख उम्मीदवारों की उम्मीदवारी वापस लेने का फैसला न केवल पार्टी के लिए असहज स्थिति लेकर आया, बल्कि इसने पूरे राजनीतिक माहौल में नई बहस छेड़ दी कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है। घटना की शुरुआत उस वक्त हुई जब नामांकन की जांच प्रक्रिया के दौरान यह सामने आया कि पार्टी द्वारा उतारी गई दो महिला उम्मीदवारों के नाम संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में दर्ज ही नहीं हैं। यह एक ऐसी बुनियादी शर्त है, जिसके बिना कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ने के योग्य नहीं माना जाता। जैसे ही यह तथ्य स्पष्ट हुआ, पार्टी के पास अपने निर्णय को वापस लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा।

इस पूरे घटनाक्रम में जिन दो नामों ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा, वे थीं लक्ष्मी प्रिया और वीना नायर। लक्ष्मी प्रिया को एर्नाकुलम जिले के पेरुम्बावूर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया था, जबकि वीना नायर को कोट्टयम जिले के एट्टुमानूर से मैदान में उतारा गया था। दोनों ही मलयालम फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री के जाने-पहचाने चेहरे हैं, और 'ट्वेंटी20' ने इन्हें मैदान में उतारकर यह संकेत देने की कोशिश की थी कि वह लोकप्रियता और जनसंपर्क के नए मॉडल पर काम कर रही है। लेकिन जैसे ही यह सामने आया कि दोनों उम्मीदवारों के नाम मतदाता सूची में मौजूद नहीं हैं, पूरी रणनीति ध्वस्त होती नजर आई। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि पार्टी के सूत्रों ने खुद स्वीकार किया कि दोनों अभिनेत्रियां पहले के चुनावों में मतदान कर चुकी हैं। ऐसे में यह सवाल और गहरा हो गया कि आखिर उनका नाम इस बार सूची से कैसे गायब हो गया। क्या यह प्रशासनिक लापरवाही है, तकनीकी गड़बड़ी है, या फिर उम्मीदवारों और पार्टी के बीच समन्वय की कमी—इन सभी पहलुओं पर अब चर्चा तेज हो चुकी है।

राजनीतिक दृष्टि से यह मामला बेहद संवेदनशील बन गया है, क्योंकि चुनाव जैसे समय में ऐसी गलती पार्टी की विश्वसनीयता पर सीधा असर डालती है। 'ट्वेंटी20' ने इस स्थिति को संभालने के लिए तुरंत कदम उठाते हुए पेरुम्बावूर सीट से नए उम्मीदवार के रूप में जिबी पथियक्कल का नाम घोषित कर दिया। हालांकि, अंतिम समय में किया गया यह बदलाव स्थानीय संगठन और कार्यकर्ताओं के लिए चुनौती बन सकता है, क्योंकि चुनावी तैयारी पहले से तय रणनीति के अनुसार चलती है और अचानक बदलाव से तालमेल बिगड़ जाता है।

यह पूरा घटनाक्रम केवल एक तकनीकी त्रुटि तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसने राजनीतिक दलों की आंतरिक प्रक्रिया और उम्मीदवार चयन के तरीके पर भी सवाल उठा दिए हैं। किसी भी उम्मीदवार को टिकट देने से पहले उसकी कानूनी और प्रशासनिक पात्रता की जांच करना एक बुनियादी प्रक्रिया होती है। ऐसे में इस स्तर की चूक यह संकेत देती है कि या तो जांच में गंभीर कमी रह गई, या फिर निर्णय जल्दबाजी में लिया गया। एनडीए के लिए यह घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि केरल में गठबंधन पहले ही अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए संघर्ष कर रहा है। ऐसे में सहयोगी दल की इस तरह की गलती विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा बन सकती है। विपक्षी दल इसे चुनावी लापरवाही और गंभीरता की कमी के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे गठबंधन की छवि पर असर पड़ सकता है। साथ ही, यह घटना मतदाताओं के बीच भी एक अलग संदेश छोड़ती है। आम जनता यह अपेक्षा करती है कि जो पार्टी शासन और व्यवस्था की बात करती है, वह खुद अपने उम्मीदवारों के चयन में पूरी सावधानी बरते। जब ऐसी बुनियादी त्रुटियां सामने आती हैं, तो विश्वास का स्तर प्रभावित होता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस घटना से सभी दलों को सीख लेने की जरूरत है। चुनाव केवल जनसमर्थन का खेल नहीं है, बल्कि यह एक सख्त प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रिया भी है, जिसमें हर नियम का पालन अनिवार्य होता है। छोटी-सी चूक भी बड़े राजनीतिक नुकसान का कारण बन सकती है।

बंगाल में सियासी तापमान चरम पर, भाजपा की दूसरी सूची ने बढ़ाई हलचल

पश्चिम बंगाल की राजनीतिक फिजा इन दिनों पूरी तरह चुनावी रंग में रंग चुकी है और हर दिन कोई न कोई बड़ा घटनाक्रम इस माहौल को और अधिक तीखा बना रहा है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी की गई दूसरी उम्मीदवार सूची ने राज्य की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। इस सूची के सामने आते ही न केवल पार्टी के भीतर हलचल तेज हुई है, बल्कि विपक्षी दलों में भी रणनीतियों को लेकर नई बेचैनी साफ महसूस की जा रही है।

भाजपा ने इस दूसरी सूची में 111 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर यह संकेत दे दिया है कि वह इस बार कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं है। इससे पहले पार्टी 144 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी थी, और अब कुल 255 सीटों पर उसके प्रत्याशी तय हो चुके हैं। केवल 39 सीटें बची हैं, जिन पर फैसला होना बाकी है। इन नामों को अंतिम रूप देने के लिए पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की कई महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं मौजूद रहे। यह बात अपने आप में बताती है कि भाजपा के लिए यह चुनाव केवल एक राज्य का चुनाव नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है।

इस सूची की सबसे चर्चित बात रही रूपा गांगुली को सोनारपुर दक्षिण से टिकट मिलना। एक समय टीवी और फिल्मों के जरिए घर-घर में पहचान बनाने वाली

रूपा गांगुली अब राजनीति में भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश में हैं। भाजपा ने उन्हें इस अहम सीट से उतारकर यह साफ कर दिया है कि वह लोकप्रिय चेहरों को चुनावी मैदान में उतारकर जनभावनाओं को अपने पक्ष में करने की रणनीति अपना रही है।

इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के भाई दिब्येंदु अधिकारी को टिकट दिया जाना भी एक बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। अधिकारी परिवार पहले ही बंगाल की राजनीति में प्रभावशाली माना जाता है, और भाजपा का यह कदम न केवल संगठन को मजबूत करने की दिशा में है, बल्कि स्थानीय स्तर पर मजबूत पकड़ बनाने की रणनीति का भी हिस्सा है।

सूची में शामिल अन्य नामों पर नजर डालें तो निसिथ प्रमाणिक को मथाभांगा, शंकर अधिकारी को चोपड़ा, कौस्तव बागची को बैरकपुर, अरूप चौधरी को कामरहाटी, रेखा पात्रा को हिंगलगंज, प्रियंका टिबरेवाल को एंटली और तपस रॉय को मानिकतला से मैदान में उतारा गया है। इन नामों का चयन यह दर्शाता है कि भाजपा हर क्षेत्र में सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार तय कर रही है, ताकि अधिकतम सीटों पर जीत सुनिश्चित की जा सके।

लेकिन इस सूची की असली चर्चा उन फैसलों को लेकर है, जो पूरी तरह चौंकाने वाले हैं। अभिनेता और नेता हिरण चटर्जी को खड़गपुर सदर से हटाकर श्यामपुर से उम्मीदवार बनाया जाना ऐसा ही एक निर्णय है। पहले उनके टिकट को लेकर अनिश्चितता बनी हुई थी, लेकिन अंतिम समय में सीट बदलने के फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया कि पार्टी अब केवल लोकप्रियता नहीं, बल्कि जीत की संभावना को प्राथमिकता दे रही है। यह बदलाव स्थानीय समीकरणों और पिछले चुनावी आंकड़ों के आधार पर किया गया माना जा रहा है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा इस बार बंगाल में पूरी ताकत के साथ उतर रही है और उसके हर फैसले के पीछे एक गहरी रणनीति काम कर रही है। उम्मीदवारों की सूची में जहां पुराने और अनुभवी नेताओं को जगह दी गई है, वहीं नए चेहरों को भी मौका देकर पार्टी ने बदलाव का संदेश देने की कोशिश की है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि भाजपा केवल चुनाव जीतने ही नहीं, बल्कि लंबे समय तक राज्य की राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ बनाना चाहती है।

दूसरी ओर, इस सूची के सामने आने के बाद विपक्षी दलों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। खासकर सत्तारूढ़ दल के लिए यह चुनौती और कठिन हो गई है, क्योंकि भाजपा अब हर सीट पर मजबूत उम्मीदवार उतारने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इससे मुकाबला पहले की तुलना में कहीं अधिक कड़ा और दिलचस्प होने की संभावना है।

अब सबकी नजर उन 39 सीटों पर टिकी हुई है, जहां भाजपा को अभी अपने उम्मीदवार घोषित करने हैं। माना जा रहा है कि इन सीटों पर भी कुछ बड़े और चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं, जो चुनावी समीकरणों को पूरी तरह बदल सकते हैं। कुल मिलाकर, भाजपा की दूसरी सूची ने यह साफ कर दिया है कि बंगाल का यह चुनाव केवल एक राजनीतिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक ऐसा संघर्ष है, जिसमें हर कदम सोच-समझकर और पूरी रणनीति के साथ उठाया जा रहा है।

आने वाले दिनों में जैसे-जैसे बाकी उम्मीदवारों के नाम सामने आएंगे और प्रचार अभियान तेज होगा, वैसे-वैसे पश्चिम बंगाल की राजनीति और भी दिलचस्प होती जाएगी। फिलहाल इतना तय है कि इस चुनाव में हर सीट पर कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी और परिणाम तक सस्पेंस बना रहेगा।

राज्यसभा की सच्चाई: दाग, दौलत और लोकतंत्र का बदलता चेहरा

देश की संसद का उच्च सदन राज्यसभा हमेशा से एक ऐसे मंच के रूप में देखा जाता रहा है जहां अनुभव, ज्ञान और नीति निर्माण की गंभीरता का संगम होता है। यह वह सदन है जहां तात्कालिक राजनीति से ऊपर उठकर दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों पर विचार किया जाता है। लेकिन हाल ही में आई एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की विस्तृत रिपोर्ट ने इस आदर्श छवि के पीछे छिपी एक जटिल और चिंताजनक वास्तविकता को उजागर कर दिया है। यह रिपोर्ट केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र के बदलते चरित्र का एक आईना बनकर सामने आई है। इस विश्लेषण में राज्यसभा के 233 में से 229 सांसदों के हलफनामों को आधार बनाया गया, जिनमें हाल ही में निर्वाचित 37 सदस्य भी शामिल हैं। जो तस्वीर उभरकर सामने आई, वह न केवल चौंकाने वाली है, बल्कि गहन चिंतन की मांग भी करती है। रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 32 प्रतिशत यानी 73 सांसदों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की जानकारी दी है। यह आंकड़ा अपने आप में एक गंभीर संकेत है कि देश के कानून बनाने वाले प्रतिनिधियों में से एक बड़ा वर्ग खुद कानून के मामलों में उलझा हुआ है। इन 73 सांसदों में से 36 ऐसे हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। गंभीर मामलों में हत्या, हत्या के प्रयास और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे संवेदनशील और कठोर आरोप शामिल हैं। एक सांसद ने हत्या का मामला घोषित किया है, जबकि चार सांसदों पर हत्या के प्रयास के आरोप हैं। तीन सांसद

ऐसे भी हैं जिन पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज हैं। जब ऐसे आरोप जनप्रतिनिधियों पर होते हैं, तो यह केवल कानूनी मुद्दा नहीं रह जाता, बल्कि यह नैतिकता और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रश्न बन जाता है। अगर इस स्थिति को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि यह समस्या किसी एक दल या विचारधारा तक सीमित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के 99 सांसदों में से 27 ने आपराधिक मामलों की घोषणा की है। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 28 में से 12 सांसद इस सूची में शामिल हैं। तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, CPI(M) और BRS जैसे दलों के सांसद भी इस प्रवृत्ति से अछूते नहीं हैं। इसका अर्थ यह है कि यह समस्या प्रणालीगत है, जो पूरे राजनीतिक ढांचे में व्याप्त हो चुकी है।

दूसरी ओर, रिपोर्ट का एक और महत्वपूर्ण पहलू है—संपत्ति का असंतुलन। लगभग 14 प्रतिशत सांसद ऐसे हैं जिनकी संपत्ति 100 करोड़ रुपये से अधिक है, यानी वे अरबपति श्रेणी में आते हैं। राज्यसभा सांसदों की औसत संपत्ति 120.69 करोड़ रुपये बताई गई है, जो यह दर्शाती है कि संसद का उच्च सदन अब आर्थिक रूप से बेहद संपन्न वर्ग का प्रतिनिधित्व करने लगा है। यह स्थिति उस देश में और भी अधिक विडंबनापूर्ण लगती है, जहां एक बड़ी आबादी अभी भी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रही है।

पार्टीवार संपत्ति के आंकड़े भी काफी दिलचस्प हैं। जहां भाजपा के सांसदों की औसत संपत्ति 28.29 करोड़ रुपये है, वहीं कांग्रेस के सांसदों की औसत संपत्ति 128.61 करोड़ रुपये बताई गई है। आम आदमी पार्टी के सांसदों की औसत संपत्ति 574.09 करोड़ रुपये तक पहुंच जाती है, जो इस बात को दर्शाती है कि कुछ दलों में अत्यधिक धनवान प्रतिनिधियों की संख्या अधिक है। इसके अलावा वाईएसआरसीपी, समाजवादी पार्टी और बीजेडी जैसे दलों के सांसदों की औसत संपत्ति भी सैकड़ों करोड़ रुपये में है।

सबसे अमीर सांसदों की सूची इस आर्थिक असमानता को और स्पष्ट करती है। बंदी पार्था सारथी ने 5,300 करोड़ रुपये से अधिक संपत्ति घोषित कर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। उनके बाद राजिंदर गुप्ता (5,053 करोड़ रुपये) और अल्ला अयोध्या रामि रेड्डी (2,577 करोड़ रुपये) जैसे नाम आते हैं। यह आंकड़े यह दर्शाते हैं कि राजनीति अब केवल सेवा का माध्यम नहीं रह गई, बल्कि यह आर्थिक शक्ति के प्रदर्शन का भी एक मंच बनती जा रही है।

इसके विपरीत, कुछ ऐसे भी सांसद हैं जिनकी संपत्ति बेहद सीमित है। संत बलबीर सिंह की संपत्ति मात्र लगभग 3 लाख रुपये है, जो उन्हें सबसे गरीब सांसद बनाती है। इसके बाद मणिपुर के महाराजा सनाजाओबा लिसेम्बा और प्रकाश चिक बड़ाइक जैसे नाम आते हैं, जिनकी संपत्ति भी कुछ लाख रुपये तक सीमित है। यह विरोधाभास लोकतंत्र के भीतर मौजूद गहरी असमानता को उजागर करता है—जहां एक ओर अरबों की संपत्ति वाले नेता हैं, वहीं दूसरी ओर बेहद साधारण आर्थिक पृष्ठभूमि से आए प्रतिनिधि भी मौजूद हैं।

अगर इस पूरे परिदृश्य को गहराई से समझा जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि भारतीय राजनीति में धन और प्रभाव का दायरा लगातार बढ़ रहा है। चुनाव लड़ना एक महंगा प्रक्रिया बन चुका है, जिसमें संसाधनों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से वही लोग आगे बढ़ते हैं जिनके पास आर्थिक ताकत और मजबूत नेटवर्क होता है। इसके साथ ही, आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों की मौजूदगी यह संकेत देती है कि राजनीति में जीतने की क्षमता को नैतिकता से अधिक महत्व दिया जा रहा है। यह स्थिति लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के लिए एक चुनौती बन सकती है। जब संसद में ऐसे प्रतिनिधि अधिक संख्या में होते हैं जिन पर आपराधिक आरोप हैं या जिनकी आर्थिक स्थिति आम जनता से बहुत अलग है, तो यह सवाल उठता है कि क्या वे वास्तव में आम लोगों की समस्याओं और जरूरतों को समझ पाएंगे।

संपादकीय

शिक्षा के अनुरूप रोजगार को गति मिले

सरकारी नौकरियों की घटती संख्या, निजी क्षेत्र की जरूरतों में बदलाव, बढ़ती आबादी तथा रोजगारपरक शिक्षा के अभाव में देश में रोजगार के अवसर कम हुए हैं। कहा जाने लगा है कि अब केवल शिक्षा ही रोजगार की गारंटी नहीं रह गई है। हाल के कुछ सर्वेक्षण इस बात की पुष्टि करते हैं। पिछले दिनों इस कटु सत्य को बयां करती 'स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2026' रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट बताती है कि देश में चालीस प्रतिशत युवा स्नातकों को बेरोजगार रहना पड़ता है। साथ ही उनमें से केवल सात फीसदी को ही एक वर्ष के भीतर स्थिर वेतन वाली नौकरियां मिल पाती हैं। निस्संदेह, हाल ही में सामने आए ये आंकड़े देश में रोजगार सृजन और उच्च शिक्षा तक पहुंच के बीच के असंतुलन को ही उजागर करते हैं। उल्लेखनीय है कि अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार, प्रत्येक वर्ष करीब पचास लाख स्नातक देश के कार्यबल में प्रवेश करते हैं। लेकिन उनमें से मुश्किल से आधे ही रोजगार पा सकते हैं। इसके साथ ही उन्हें कम सुरक्षित व कम वेतन वाली नौकरियां ही मिलती हैं। निश्चय ही दुनिया की सबसे अधिक युवा आबादी वाले देश के लिये यह सुखद संकेत नहीं कहा सकता है। अन्य शब्दों में कहें तो स्नातक होने और रोजगार के अवसरों के बीच व्याप्त असंतुलन के चलते भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश के कालांतर जनसांख्यिकीय दायित्व में तब्दील होने का खतरा पैदा हो रहा है। जिसे देश के नीति-नियंताओं को गंभीरता से लेना चाहिए। विशेषज्ञों का अनुमान है कि देश में कामकाजी उम्र की आबादी के साल 2030 से पहले चरम पर पहुंचने का आकलन है। इस स्थिति में चिंता जतायी जा रही है कि देश में युवा ऊर्जा के सदुपयोग करने का अवसर तेजी से कम होता जा रहा है। निर्विवाद रूप से यदि भविष्य में पर्याप्त और लाभकारी रोजगार के अवसर पैदा नहीं किए जाते हैं तो देश में बेरोजगारी बढ़ने से युवाओं के कुंठित होने का खतरा पैदा हो सकता है। वहीं दूसरी ओर भारतीय रोजगार परिदृश्य पर नजर रखने वाले विशेषज्ञ चिंता जता रहे हैं कि देश को शिक्षित युवाओं में लगातार बढ़ती निराशा, स्थिर आय और धीमी आर्थिक गतिशीलता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वास्तव में यहां प्रश्न केवल संख्या का ही नहीं है वरन यह रोजगार की गुणवत्ता का भी सवाल है। देश में कई स्नातक ऐसे संस्थानों से निकलते हैं, जो शिक्षकों की कमी, पुराने पाठ्यक्रम और कमजोर उद्योग संबंधों जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। विडंबना यह भी है कि देश में कुशल श्रम को रोजगार देने में सक्षम क्षेत्र, मसलन विनिर्माण और उच्च मूल्य वाली सेवाएं पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हुई हैं। इसका परिणाम यह है कि डिग्री की संख्या रोजगार बाजार में मांग की संख्या के अनुपात में कहीं अधिक है। वहीं दूसरी ओर, निर्विवाद रूप से देश के रोजगार बाजार में सकारात्मक रूप से भी प्रगति के संकेत मिल रहे हैं। जाति और लिंग से जुड़ी व्यावसायिक बाधाएं धीरे-धीरे कम हो रही हैं। हालांकि, रोजगार सृजन में समांतर वृद्धि के बिना ये उपलब्धियां महत्वहीन ही होंगी। यह भी हकीकत है कि मौजूदा परिदृश्य में देश को नामांकन बढ़ाने की प्राथमिकता से हटकर रोजगार क्षमता बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो व्यावसायिक प्रशिक्षण में निवेश बढ़ाने, उद्योग तथा अकादमिक साझेदारी को दृढ़ता देने की दिशा में काम करने तथा श्रम प्रधान क्षेत्रों को मजबूत करने की जरूरत होगी। निश्चित रूप से जब हम श्रम प्रधान क्षेत्रों को प्रभावी बनाने का प्रयास करेंगे तो रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो सकेगी। इसके साथ ही यह भी जरूरी होगा कि देश की आर्थिक नीति को तेजी से बढ़ते शिक्षित कार्यबल की वास्तविकताओं के अनुरूप बनाया जाए। हमारे नीति नियंताओं के सामने चुनौती बिल्कुल स्पष्ट है कि देश की अर्थव्यवस्था में यह सुनिश्चित किया जाए कि शिक्षा का लाभ यूं ही व्यर्थ न चला जाए।

Iran बना नये पुराने हथियारों की 'प्रयोगशाला' Live Lab के परिणाम देख पूरी दुनिया दंग

> यदि अमेरिका और इज़राइल की ओर से प्रयुक्त हथियारों की बात करें, तो इनमें अत्याधुनिक ड्रोन, साइबर हथियार, स्टेल्थ तकनीक से लैस लड़ाकू विमान और प्रिसीजन-गाइडेड मिसाइलें प्रमुख हैं। उदाहरण के लिए **MQ**-9 रीपर जैसे ड्रोन निगरानी और सटीक हमलों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।

ईरान पर हुए हमले के बाद जो भू-राजनीतिक तनाव उभरा है, उसने आधुनिक युद्ध की प्रकृति को समझने का एक नया अवसर भी दिया है। विशेषकर अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच बढ़ते टकराव ने इस क्षेत्र को उन्नत सैन्य तकनीकों के परीक्षण-स्थल जैसा बना दिया है। इस संघर्ष में कई आधुनिक और विकसित हथियारों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग देखने को मिल रहा है जो दुनिया के तमाम देशों को अपनी अपनी सैन्य रणनीतियों पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर रहा है। सबसे पहले यदि अमेरिका और इज़राइल की ओर से प्रयुक्त हथियारों की बात करें, तो इनमें अत्याधुनिक ड्रोन, साइबर हथियार, स्टेल्थ तकनीक से लैस लड़ाकू विमान और प्रिसीजन-गाइडेड मिसाइलें प्रमुख हैं। उदाहरण के लिए MQ-9 रीपर जैसे ड्रोन निगरानी और सटीक हमलों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह, इज़राइल की आयरन डोम जैसी मिसाइल रक्षा प्रणाली ने दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया है, जो आने वाली रॉकेट और मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने की क्षमता रखती है। इसके अलावा, साइबर युद्ध के क्षेत्र में भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाने के लिए स्टक्सनेट जैसे वायरस का उपयोग किया गया, जो आधुनिक युद्ध की नई दिशा को दर्शाता है। दूसरी ओर, ईरान ने भी अपने सीमित संसाधनों के बावजूद असममित युद्ध रणनीति अपनाई है। ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों का एक बड़ा जखीरा है, जैसे शाहाब और फतेह सीरीज, जो क्षेत्रीय स्तर पर प्रभावी मानी जाती हैं। इसके अलावा, ईरान ने ड्रोन तकनीक में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। शाहेद सीरीज के ड्रोन, जिन्हें कामीकाजे ड्रोन भी कहा जाता है, दुश्मन के

ठिकानों पर सीधा हमला करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये सस्ते, लेकिन प्रभावी हथियार हैं, जिनका उपयोग ईरान और उसके सहयोगी समूहों द्वारा व्यापक रूप से किया गया है। ईरान की नौसैनिक रणनीति भी उल्लेखनीय है। फारस की खाड़ी जैसे संकरे समुद्री मार्ग में ईरान छोटी, तेज गति वाली नौकाओं, समुद्री माइंस और एंटी-शिप मिसाइलों का उपयोग करता है। यह रणनीति बड़े और महंगे युद्धपोतों के मुकाबले कम लागत में अधिक प्रभाव पैदा करने पर आधारित है। इसके अलावा, ईरान ने सुरंगों और भूमिगत ठिकानों का एक जाल भी विकसित किया है, जिससे उसके हथियार और मिसाइल सिस्टम सुरक्षित रहते हैं। इस युद्ध में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह उभरकर सामने आया है कि ईरान द्वारा इस्तेमाल किए गए कुछ चीनी मूल के हथियार अपेक्षित प्रभाव नहीं दिखा सके। इन प्रणालियों की सीमाएँ जैसे सटीकता, विश्वसनीयता या इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के सामने इनके टिकाऊपन ने विश्लेषकों के बीच यह चर्चा तेज कर दी है कि इससे चीन की रक्षा निर्यात छवि पर असर पड़ सकता है। हम आपको बता दें कि चीन लंबे समय से एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व के देशों को किफायती हथियार उपलब्ध कराकर एक बड़े रक्षा आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है, लेकिन यदि उसके हथियार वास्तविक संघर्ष परिस्थितियों में कमजोर साबित होते हैं, तो संभावित खरीदार देशों का विश्वास डगमगा सकता है। यही कारण है कि ऐसी रिपोर्टें चीन के लिए रणनीतिक चिंता का विषय बन रही हैं, क्योंकि रक्षा निर्यात न केवल आर्थिक लाभ का स्रोत है बल्कि वैश्विक प्रभाव और कूटनीतिक संबंधों का भी महत्वपूर्ण साधन है।

सामरिक दृष्टि से देखें तो इस युद्ध ने "हाइब्रिड वारफेयर" की अवधारणा को और स्पष्ट किया है। इसमें पारंपरिक सैन्य ताकत के साथ-साथ साइबर हमले, प्रॉक्सी युद्ध, सूचना युद्ध और आर्थिक प्रतिबंध भी शामिल होते हैं। अमेरिका और इज़राइल जहां तकनीकी श्रेष्ठता के बल पर सटीक और सीमित हमले करते हैं, वहीं ईरान अपनी रणनीति में लचीलापन और व्यापकता बनाए रखता है। यह असमान शक्ति संतुलन को संतुलित करने का एक प्रयास है।

रणनीतिक महत्व की दृष्टि से, यह पूरा परिदृश्य कई महत्वपूर्ण संकेत देता है। एक तो आधुनिक युद्ध अब केवल मैदान में लड़े जाने वाले संघर्ष तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह तकनीक, सूचना और मनोवैज्ञानिक प्रभाव तक फैल चुका है। इसके अलावा, छोटे और मध्यम शक्ति वाले देश भी अब उन्नत तकनीकों के माध्यम से बड़ी शक्तियों को चुनौती देने में सक्षम हो रहे हैं। साथ ही, ड्रोन और साइबर हथियार जैसे साधन युद्ध की लागत को कम करते हुए उसकी जटिलता को बढ़ा रहे हैं।

इसके अलावा, इस क्षेत्र में हो रहे हथियारों के उपयोग का वैश्विक प्रभाव भी है। विभिन्न देश इन तकनीकों का अध्ययन कर अपनी सैन्य नीतियों को पुनर्गठित कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, ड्रोन युद्ध की सफलता ने कई देशों को इस दिशा में निवेश बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। इसी तरह, मिसाइल रक्षा प्रणालियों की उपयोगिता ने भी रक्षा बजट और रणनीतियों को प्रभावित किया है।

बहरहाल, यह कहा जा सकता है कि ईरान और उसके आसपास का क्षेत्र आधुनिक युद्ध की बदलती प्रकृति का एक जीवंत उदाहरण बन चुका है। यहां हो रहे संघर्ष केवल क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को ही नहीं, बल्कि वैश्विक सैन्य रणनीतियों और तकनीकी विकास की दिशा को भी प्रभावित कर रहे हैं। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये प्रयोग किस प्रकार अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और शांति व्यवस्था को आकार देते हैं।

प्रेरणा

अटूट जिज्ञासा और निरंतर प्रयास से जन्म लेता समाधान

मानव जीवन में समस्याएँ कोई नई बात नहीं हैं, बल्कि वे हमारी सोच, धैर्य और बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने का एक माध्यम होती हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिन लोगों ने समस्याओं से भागने के बजाय उनका सामना किया, उन्होंने ही ऐसे अद्भुत समाधान खोजे जो पूरी मानवता के लिए मार्गदर्शक बन गए। इसी संदर्भ में Archimedes की एक प्रसिद्ध घटना हमें यह सिखाती है कि जब मन पूरी तरह किसी समस्या में डूब जाता है, तो उसका समाधान भी उतनी ही सहजता से उभरकर सामने आता है, भले ही वह क्षण अचानक ही क्यों न आए।

सायराक्यूज के राजा के सामने एक कठिन प्रश्न था। उसने एक स्वर्ण मुकुट बनवाया था, लेकिन उसे संदेह था कि उसमें शुद्ध सोने के स्थान पर कोई अन्य धातु मिलाई गई है। समस्या यह थी कि बिना मुकुट को नुकसान पहुँचाए उसकी शुद्धता की जांच कैसे की जाए। यह कार्य आर्किमिडीज को सौंपा गया, जो अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने इस समस्या पर कई दिनों तक गहन विचार किया, विभिन्न तरीकों पर चिंतन किया, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं मिल पाया। यह स्थिति किसी भी जिज्ञासु व्यक्ति के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण होती है, क्योंकि जब लगातार प्रयास के बावजूद उत्तर न मिले, तो मन में निराशा का भाव आना स्वाभाविक है।

लेकिन यहीं से आर्किमिडीज की विशेषता सामने आती है। उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि अपने मन को पूरी तरह उसी समस्या में लगाए रखा। उनका ध्यान हर समय उसी प्रश्न पर केंद्रित था, चाहे वे कुछ भी कर रहे हों। यह वही अवस्था होती है जब व्यक्ति का अवचेतन मन भी समाधान खोजने में सक्रिय हो जाता है। कई बार हम किसी समस्या को सुलझाने के लिए जितना अधिक दबाव डालते हैं, उतना ही समाधान दूर होता जाता है, लेकिन जब हम शांत होकर उसे सोचते रहते हैं, तो उत्तर अचानक सामने आ जाता है। एक दिन जब आर्किमिडीज स्नान करने के लिए टब में बैठे, तो उन्होंने एक साधारण सी घटना पर ध्यान दिया। जैसे-जैसे उनका शरीर पानी में डूब रहा था, पानी बाहर निकल रहा था। यह एक सामान्य अनुभव था, जिसे हम सभी ने कभी न कभी महसूस किया होगा, लेकिन फर्क यह था कि आर्किमिडीज का मन उस समय भी उसी समस्या में लगा हुआ था। उन्होंने तुरंत इस घटना को अपनी समस्या से जोड़ा और समझ लिया कि किसी भी वस्तु का आयतन उसके द्वारा विस्थापित किए गए पानी से मापा जा सकता है। यही वह क्षण था जब उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया।

उनकी खुशी इतनी अधिक थी कि वे तुरंत ही टब से बाहर निकलकर सड़कों पर दौड़ पड़े और 'यूरेका! यूरेका!' चिल्लाने लगे, जिसका अर्थ होता है 'मिल गया! मिल गया!' यह केवल एक शब्द नहीं था, बल्कि उस गहन प्रयास, धैर्य और एकाग्रता का परिणाम था जो उन्होंने उस समस्या के समाधान के लिए लगाया था। बाद में इसी सिद्धांत का उपयोग करके उन्होंने यह सिद्ध किया कि मुकुट में मिलावट की गई थी या नहीं।

यह घटना केवल एक वैज्ञानिक खोज की कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक गहरा संदेश देती है। यह हमें बताती है कि समाधान हमेशा हमारे आसपास ही होता है, लेकिन उसे देखने के लिए हमें सही दृष्टिकोण और धैर्य की आवश्यकता होती है। जब हम किसी समस्या को लेकर गंभीर होते हैं और लगातार उसके बारे में सोचते रहते हैं, तो हमारा मन हर छोटी-बड़ी घटना को उसी संदर्भ में देखने लगता है, और यही प्रक्रिया हमें समाधान तक पहुँचाती है।

आज के समय में, जब लोग त्वरित परिणाम चाहते हैं, यह कहानी हमें सिखाती है कि हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं मिलता। कई बार हमें लंबे समय तक प्रयास करना पड़ता है, असफलताओं का सामना करना पड़ता है, और धैर्य बनाए रखना पड़ता है। लेकिन यदि हमारा प्रयास निरंतर और सच्चा है, तो अंततः सफलता अवश्य मिलती है। यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अपने मन को तनावमुक्त रखें, क्योंकि कई बार समाधान तब मिलता है जब हम उसे खोजने का प्रयास नहीं कर रहे होते, बल्कि हमारा मन शांत और खुला होता है।

इस घटना से यह भी स्पष्ट होता है कि रचनात्मकता और खोज केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं होती। वह हमारे दैनिक जीवन के साधारण अनुभवों में भी छिपी होती है। फर्क केवल इतना है कि हम उन्हें किस दृष्टि से देखते हैं। आर्किमिडीज ने एक साधारण स्नान के अनुभव को एक महान वैज्ञानिक सिद्धांत में बदल दिया, क्योंकि उनका मन सजग और जिज्ञासु था।

जीवन में यदि हम भी इसी दृष्टिकोण को अपनाएं, तो हम अपनी समस्याओं को एक नए नजरिए से देख पाएंगे। हमें यह समझना होगा कि हर कठिनाई एक अवसर है, जो हमें कुछ नया सिखाने और आगे बढ़ने का मौका देती है। जब हम समस्याओं से घबराने के बजाय उन्हें समझने का प्रयास करते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है और हमारी सोच भी व्यापक होती है।

अंततः, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समाधान पाने के लिए केवल बुद्धि ही नहीं, बल्कि धैर्य, निरंतरता और एकाग्रता भी उतनी ही आवश्यक है। जब ये सभी गुण एक साथ मिलते हैं, तो कोई भी समस्या असंभव नहीं रहती। आर्किमिडीज की तरह यदि हम भी अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखें और अपने मन को जिज्ञासु बनाए रखें, तो जीवन की हर चुनौती हमारे लिए एक नई खोज का द्वार बन सकती है।

जनभागीदारी व जागरूकता से शुद्ध होगा गंगाजल

गंगा नदी आज भी अपनी शुद्धि की बाट जोह रही है। राजीव गांधी के सत्तासीन होने के बाद 1986 में गंगा एक्शन प्लान लागू हुआ था, लेकिन उसके बावजूद गंगा शुद्धि के नाम पर खर्च किए गए हजारों करोड़ रुपये भी उसे प्रदूषण से मुक्त नहीं कर पाए। आज भी गंगा का जल आचमन के लायक नहीं रह गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की उत्तराखंड में नमामि गंगे कार्यक्रम पर केंद्रित 2018-2023 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट गंगा की बदहाली को ही दर्शाती है। कैग की रिपोर्ट हाल ही में राज्य विधानसभा के बजट सत्र में पटल पर रखी गई थी। रिपोर्ट के अनुसार, गोमुख से लेकर देवप्रयाग तक गंगा का पानी आचमन योग्य यानी 'ए' श्रेणी का है, जबकि ऋषिकेश और हरिद्वार तक उसका पानी नहाने योग्य यानी 'बी' श्रेणी का है। कैग रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार ने गंगातट पर बसे शहरों में सीवेज सुविधाओं में वृद्धि के लिए धन आवंटित नहीं किया। रिपोर्ट में यह भी दर्शाया गया है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के डिज़ाइन में खामियां, इंफ्रास्ट्रक्चर का खराब रखरखाव, गंगा में गिरने वाले नालों को रोकने में नाकामी और नदियों तथा धाराओं में कचरा फेंके जाने पर अंकुश लगाने में असफलताएं रही हैं। कैग की रिपोर्ट में, 'नमामि गंगे' योजना की विफलताएं सामने आई हैं। उदाहरण के लिए, वानिकी हस्तक्षेप का मामला, जिसमें 885.91 करोड़ रुपये का बजट रखा गया था, परंतु निर्धारित लक्ष्य के विपरीत कोई सार्थक कार्रवाई नहीं की गई। जिन पेड़ों को लगाने का लक्ष्य था, उनके लिए आवंटित धन का एक भी हिस्सा सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च नहीं किया गया। न तो एसटीपी बने, न ही घरों को सीवर कनेक्शन दिए गए। चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी में 11 श्मशान घाटों का निर्माण हुआ, जो न तो प्रयोग में लाए गए हैं और न ही उनका ठीक से रखरखाव किया गया है।

राज्य के अधिकारियों ने गंगा के संरक्षण के लिए 2020 तक कोई ठोस योजना नहीं बनाई और गंगा में गंदा पानी और औद्योगिक कचरा गिरने से रोकने में नाकामी रही। गंगा किनारे बसे सात शहरों में बने 21 एसटीपी में से एक भी घर का सीवेज इनसे नहीं जुड़ा। हरिद्वार और ऋषिकेश में ओवरलोडिंग की समस्या तो बढ़ी ही, वहीं जोशीमठ और देवप्रयाग में सीवेज का बहाव भी घट गया। इससे यह साफ है कि एसटीपी अपने उद्देश्य में विफल रहे हैं।

गंगा के संरक्षण के लिए जर्मन डेवलपमेंट बैंक जैसी संस्थाओं द्वारा दिया गया फंड भी सिर्फ हरिद्वार और ऋषिकेश तक ही सीमित रहा। ऋषिकेश के ढालवाला, कीर्तिनगर, रुद्रप्रयाग, श्रीकोट, गोपेश्वर और कर्णप्रयाग जैसे स्थानों पर 12 एसटीपी बिना ट्रीट किए गंदा पानी गंगा में बहा रहे हैं। 44 एसटीपी में से 8 एसटीपी चार साल से अधिक समय तक बिना पीसीबी की मंजूरी के संचालित हो रहे हैं। 18 एसटीपी अभी तक उत्तराखंड जल संस्थान को सौंपे ही नहीं गए हैं। ये सभी गंगा की शुद्धि के लिए बनी योजनाओं की नाकामी के प्रतीक हैं।

गंगा की यह बदहाली जब उत्तराखंड में है, तो उसके बहाव क्षेत्र जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में तो स्थिति का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। गंगा के बहाव क्षेत्र के अधिकांश स्थानों पर कोलिफार्म बैक्टीरिया की मात्रा मानक से 45 गुणा से भी अधिक पाई गई है। एनजीटी ने भी माना है कि गंगा के 60 फीसदी हिस्से में बिना ट्रीटमेंट के गंदगी गिराई जा रही है। गंगा में सॉलिड और लिक्विड वेस्ट गिरने के कारण और टोटल कोलिफार्म एवं फीकल कोलिफार्म का स्तर अत्यधिक बढ़ गया है। इसके कारण चर्म रोगों के मामलों में वृद्धि हो रही है। गंगाजल में ऐसे जीवाणु पाए गए हैं जिन पर एंटीबायोटिक दवाओं का भी असर नहीं होता। शोधों में यह भी खुलासा हुआ है कि गंगा बेसिन में माइक्रोप्लास्टिक का अत्यधिक प्रसार हो चुका है, जो पारिस्थितिकी तंत्र, जल स्रोतों और जीव-जंतुओं के लिए भी गंभीर खतरा है। माइक्रोप्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं होता और पर्यावरण में जमा हो जाता है, जो समुद्री तंत्र और प्राणी जगत के लिए भी एक भयंकर समस्या है।

यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एनर्जी पालिसी इंस्टीट्यूट के शोध में यह पाया गया कि गंगा किनारे के प्रदूषित इलाकों में प्रदूषण बढ़ने से लोगों की उम्र कम हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, एंटीबायोटिक्स के बेअसर होने के कारण बैक्टीरिया होने से हर साल सात लाख मौतें होती हैं। धार्मिक कारणों से लाखों श्रद्धालु गंगा में स्नान करते हैं और उसका जल आचमन करते हैं। इसके कारण गंगाजल में घुले एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया उनके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं।

गंगा शुद्धीकरण के अभियान में केंद्र सरकार के सात मंत्रालयों की साख दांव पर है। असल में, गंगा तब तक शुद्ध नहीं हो सकती जब तक स्थानीय निकाय ईमानदारी से अपनी भूमिका का निर्वहन न करें और इस अभियान में जनभागीदारी को अहमियत न दी जाए। सबसे महत्वपूर्ण सवाल देश की धर्मपरायण जनता की जागरूकता का है।

अभियान

जब भक्त का क्रोध भी बन गया भगवान की लीला का साधन

सनातन धर्म की कथाओं में ऐसी अनेक लीलाएँ वर्णित हैं, जिनमें भगवान और उनके भक्तों के बीच घटित घटनाएँ केवल बाहरी दृष्टि से देखने पर सामान्य प्रतीत होती हैं, लेकिन उनके भीतर गहरे आध्यात्मिक रहस्य छिपे होते हैं। ऐसी ही एक अद्भुत और चिंतनशील कथा है Narad Muni और Lord Vishnu के बीच घटित वह प्रसंग, जिसमें एक ओर भक्त का क्रोध है, तो दूसरी ओर भगवान की करुणा और दिव्य योजना का रहस्य।

देवर्षि नारद सदा भगवान के परम भक्त माने जाते हैं। वे तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए हर क्षण 'नारायण-नारायण' का कीर्तन करते रहते हैं। उनका जीवन वैराग्य, ज्ञान और भक्ति का अद्भुत संगम है। किंतु इस कथा में हमें उनके जीवन का एक ऐसा पक्ष देखने को मिलता है, जहाँ वे भी माया और अहंकार के प्रभाव में आ जाते हैं। यही इस लीला का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि यह हमें यह समझने का अवसर देती है कि साधना के उच्चतम स्तर पर पहुँचा हुआ व्यक्ति भी यदि सजग न रहे, तो वह माया के जाल में फँस सकता है।

एक समय की बात है, जब नारद मुनि एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी के स्वयंवर में पहुँचे। उस राजकुमारी का रूप इतना आकर्षक था कि उसे देखकर नारद मुनि के मन में भी उसे पाने की इच्छा उत्पन्न हो गई। यह इच्छा धीरे-धीरे उनके भीतर आसक्ति में बदल गई। यही वह बिंदु था, जहाँ उनकी तपस्या की परीक्षा आरंभ हुई। उन्होंने सोचा कि यदि उन्हें भगवान विष्णु के समान सुंदर रूप प्राप्त हो जाए, तो वे निश्चित रूप से उस राजकुमारी का वरण कर सकते हैं। इस विचार के साथ वे तुरंत भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना की कि वे उन्हें अपना स्वरूप प्रदान करें। भगवान विष्णु मुस्कराए और उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, किंतु उनकी लीला कुछ और ही थी। उन्होंने नारद मुनि को ऐसा रूप दिया, जो उन्हें स्वयं तो अत्यंत सुंदर प्रतीत हो, लेकिन अन्य लोगों को वह वानर जैसा दिखाई दे। यह भगवान की माया थी, जो केवल बाहरी रूप ही नहीं, बल्कि दृष्टि को भी प्रभावित कर देती है।

नारद मुनि बड़े आत्मविश्वास के साथ स्वयंवर में पहुँचे। उन्हें विश्वास था कि राजकुमारी उन्हें ही चुनेगी। लेकिन जैसे ही वे वहाँ पहुँचे, लोगों ने उनका उपहास करना शुरू कर दिया। राजकुमारी ने भी उन्हें देखकर हँसी उड़ाई और अंततः भगवान विष्णु के ही एक अन्य रूप को वरण कर लिया। यह देखकर नारद मुनि के हृदय में तीव्र आघात लगा। उनका अहंकार टूट गया और उनके भीतर क्रोध की ज्वाला भड़क उठी।

क्रोध के उसी आवेग में उन्होंने भगवान विष्णु को कठोर वचन कहे और उन्हें श्राप दे दिया कि जिस रूप से उन्होंने उन्हें ठगा है, उसी रूप को उन्हें भी धारण करना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जैसे उन्होंने उनका उपहास कराया, वैसे ही उन्हें भी स्त्री-वियोग का दुःख सहना पड़ेगा और वानर ही उनकी सहायता करेंगे। यह श्राप आगे चलकर भगवान के Lord Rama अवतार में सत्य हुआ, जब उन्हें माता सीता के वियोग का दुःख सहना पड़ा और वानर सेना ने उनकी सहायता की।

यहाँ सबसे अद्भुत बात यह है कि भगवान विष्णु ने इस श्राप को न केवल स्वीकार किया, बल्कि उसे अपनी लीला का एक हिस्सा बना लिया। उन्होंने न तो नारद मुनि के क्रोध का प्रतिकार किया और न ही कोई नाराजगी दिखाई। वे मंद मुस्कान के साथ सब कुछ सहते रहे। यह भगवान के उस दिव्य स्वभाव को दर्शाता है, जिसमें वे अपने भक्त के हर भाव को प्रेमपूर्वक स्वीकार करते हैं।

जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, तब नारद मुनि को सच्चाई का बोध हुआ। उन्होंने देखा कि वहाँ न कोई राजकुमारी थी और न ही कोई वास्तविक स्वयंवर—सब कुछ भगवान की रची हुई माया थी। यह देखकर वे अत्यंत भयभीत हो गए और उनका अहंकार पूरी तरह समाप्त हो गया। वे तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़े और अपने कटु वचनों के लिए क्षमा माँगने लगे। यह क्षण किसी भी साधक के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जब व्यक्ति अपने अहंकार को त्यागकर ईश्वर के सामने समर्पण कर देता है, तभी उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। नारद मुनि के साथ भी यही हुआ। उनका क्रोध शांत हो गया और उनके हृदय में पश्चाताप और भक्ति का भाव जागृत हो गया।

भगवान विष्णु ने उन्हें प्रेमपूर्वक उठाया और कहा कि यह सब उनकी ही इच्छा से हुआ है। उन्होंने नारद मुनि को भगवान शंकर के शतनाम का जप करने की सलाह दी, जिससे उनके हृदय को शांति मिल सके। यहाँ भगवान द्वारा Lord Shiva के नामों का स्मरण करने का निर्देश देना यह दर्शाता है कि सभी देवताओं में कोई भेद नहीं है, बल्कि वे सभी एक ही परम सत्य के विभिन्न रूप हैं।

इस कथा का एक और गहरा अर्थ यह है कि भगवान अपने भक्तों के दोषों को भी उनके कल्याण का साधन बना देते हैं। नारद मुनि का क्रोध और अहंकार, जो सामान्यतः दोष माने जाते हैं, इस लीला के माध्यम से उनके आत्मज्ञान का कारण बन गए। भगवान ने उनके भीतर छिपे अहंकार को बाहर निकालने के लिए यह लीला रची, ताकि वे और भी शुद्ध और निर्मल हो सकें।

यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि क्रोध में किया गया कार्य और बोले गए शब्द कितने दूरगामी प्रभाव डाल सकते हैं। नारद मुनि जैसे महान ऋषि भी जब क्रोध के वश में आए, तो उन्होंने ऐसा श्राप दे दिया, जिसका प्रभाव भगवान के अवतार तक पहुँचा। इसलिए मनुष्य को अपने भावों पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है।

साथ ही, यह कथा यह भी बताती है कि ईश्वर की माया कितनी सूक्ष्म और शक्तिशाली होती है। वह न केवल हमारी आँखों को भ्रमित करती है, बल्कि हमारे विचारों और भावनाओं को भी प्रभावित कर सकती है। इससे बचने का एकमात्र उपाय है—निरंतर भक्ति, विनम्रता और आत्मचिंतन।

अंततः, यह लीला हमें यह विश्वास दिलाती है कि भगवान का हर कार्य हमारे कल्याण के लिए होता है। भले ही उस समय हमें वह समझ में न आए, लेकिन समय के साथ उसका उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। भगवान अपने भक्तों को कभी भी संकट में नहीं छोड़ते, बल्कि हर परिस्थिति में उनका मार्गदर्शन करते हैं।

इस प्रकार, नारद मुनि और भगवान विष्णु की यह कथा केवल एक पुराणिक प्रसंग नहीं है, बल्कि यह जीवन के गहरे सत्य को प्रकट करने वाली एक दिव्य शिक्षा है। यह हमें सिखाती है कि अहंकार और क्रोध से बचना चाहिए, भक्ति और विनम्रता को अपनाना चाहिए, और हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं, तब हमारे जीवन की हर चुनौती एक नई सीख और एक नई दिशा प्रदान करती है, और हम धीरे-धीरे उस परम सत्य के निकट पहुँचने लगते हैं, जहाँ केवल शांति, प्रेम और आनंद का वास होता है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की गरिमामय वर्चुअल उपस्थिति में पोरबंदर जिले के 413.81 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की वर्चुअली अध्यक्षता में गुरुवार को पोरबंदर शहर के ताजावाला हॉल में विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास व लोकार्पण का समारोह आयोजित हुआ।

मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़कर पोरबंदर जिले के नागरिकों को कुल 413.81 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के लगभग 46 विकास कार्यों की भेंट दी। इन परियोजनाओं के अंतर्गत लगभग 329.59 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले 17 विकास कार्यों का ई-शिलान्यास तथा 93.22 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण हुए 29 विकास कार्यों का ई-लोकार्पण किया गया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने पोरबंदर जिले के नागरिकों को वीडियो के माध्यम से शुभकामना प्रेषित कर 'विकास भी, विरासत भी' के मंत्र को सार्थक करने वाली विकास परियोजनाओं की भेंट दी। इस अवसर पर श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में समग्र राज्य में शहरी सुविधा के सर्वांगीण विकास कार्य तेज गति से किए जा रहे हैं। इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए पोरबंदर नगर पालिका को महानगर पालिका का दर्जा देकर उसके आधुनिकीकरण के लिए लगभग 291 करोड़ रुपए की बड़ी राशि आवंटित की गई है। समग्र जिले के लिए कुल 414 करोड़ रुपए से अधिक के विकासोन्मुखी कार्यों का आयोजन किया गया।

वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया

- हम पोरबंदर को विकास की दृष्टि से एक मॉडल जिला बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और सरकार सभी विकास कार्यों के गुणवत्तायुक्त होने के प्रति सतर्क है
- मुख्यमंत्री के करकमलों से शिलान्यास के साथ 20 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाला 'सौंदर्य वन' प्रोजेक्ट पोरबंदर को पर्यावरण एवं पर्यटन क्षेत्र में नई पहचान दिलाएगा

उन्होंने कहा कि इस विकास यात्रा में सरकार का केवल भौतिक अवसंरचना के निर्माण का ही नहीं; अपितु 'सर्वोदय वन' तथा 'मोकर सागर वेटलैंड' जैसी परियोजनाओं द्वारा इको-टूरिज्म को भी गति देने का संकल्प है। इसके अतिरिक्त; ग्रामीण क्षेत्रों में पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) अंतर्गत 20 करोड़ रुपए की लागत से विद्युत सुविधाएँ सुदृढ़ की गई हैं और युवाओं के कौशलवर्धन के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) में नए भवनों का निर्माण भी किया गया है।

मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक दृष्टि से पोरबंदर के महत्व को उजागर करते हुए कहा कि आगामी रामनवमी से शुरू होने वाला माधवपुर का मेला केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण एवं रुक्मिणीजी के विवाह प्रसंग द्वारा पश्चिम भारत तथा उत्तर-पूर्वी भारत के राज्यों को जोड़ने वाला 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' का अटूट सेतु है। राज्य सरकार पूज्य गांधी बापू की इस जन्मभूमि पर स्वच्छता एवं सेवा के मूल्यों के साथ वर्ष 2047 तक 'विकसित गुजरात से विकसित भारत' के संकल्प को साकार करने के लिए दृढ़ है। श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि सरकार के सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन के चलते विकास के कार्यों के सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि वे इस विकास यात्रा में सहभागी हों और विकसित गुजरात के लिए पोरबंदर को लीड लेने वाला महानगर बनाएँ। उन्होंने पोरबंदर में नए बनने जा रहे सांस्कृतिक वन के संदर्भ में कहा कि संयोग से वन मंत्री भी पोरबंदर के हैं और उनके समन्वय में हो रहे वन एवं पर्यावरण के तथा बरडा डुंगर (पर्वत) व इस क्षेत्र के पर्यावरणोन्मुखी विकास कार्यों से इस जिले का विकास पर्यावरण के संतुलन के साथ आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी की जन्मभूमि तथा सुदामा की नगरी पोरबंदर में भव्य सांस्कृतिक विरासतें हैं। उनके महत्व को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने पोरबंदर जिले के सर्वांगीण विकास के लिए श्रृंखलाबद्ध आयोजन किया है। राज्य सरकार ने पोरबंदर जिले में पिछले 5 वर्षों में 2100 करोड़ रुपए के कार्य किए हैं।

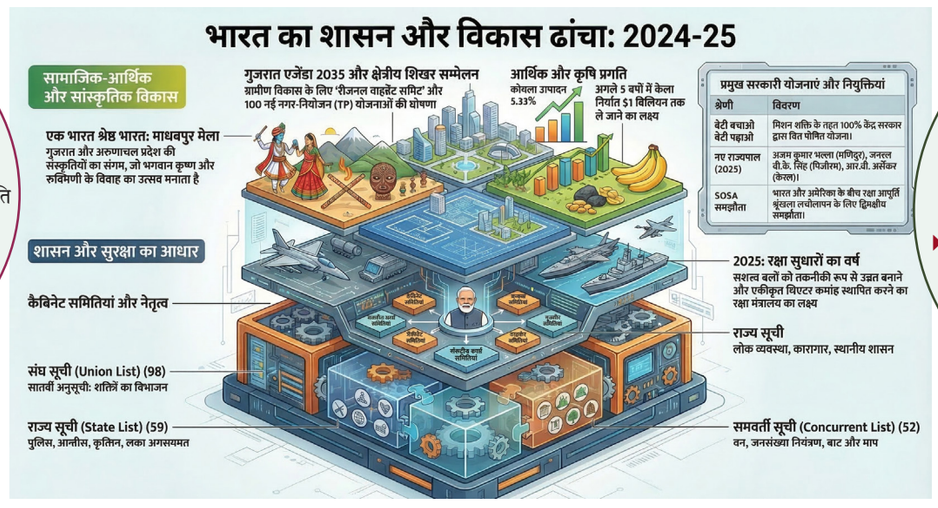

श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार पोरबंदर जिले के सर्वांगीण विकास के लिए कटिबद्ध है।

श्री मोढवाडिया ने विशेष संज्ञान लिया कि पोरबंदर शहर में आधुनिक सुविधाओं के लिए भारी धन राशि आवंटित की गई है; जिसमें स्ट्रीट लाइट के लिए 55 करोड़ रुपए, छाया आइकॉनिक रोड के लिए 16 करोड़ रुपए तथा ऐतिहासिक लाइब्रेरी के हेरिटेज रीस्टोरेशन के लिए 5 करोड़ रुपए शामिल हैं। इसके अतिरिक्त; उन्होंने जिले के विद्यार्थियों तथा युवाओं के लिए आगामी बजट में 100 करोड़ रुपए की लागत से 'रीजनल साइंस सेंटर' की मंजूरी देने के लिए मुख्यमंत्री का विशेष आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दिशादर्शन में वर्ष 2047 तक 'विकसित गुजरात से विकसित भारत' के संकल्प को साकार करने के लिए राज्य सरकार दृढ़ है
- सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन के चलते विकास कार्यों के लिए सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है
- राज्य सरकार द्वारा भव्य सांस्कृतिक विरासतों को ध्यान में रखकर पोरबंदर का सर्वांगीण विकास किया जा रहा है
- हमारी भव्य विरासत को उजागर करने वाला माधलपुर घेड का मेला आगामी रामनवमी से शुरू होने वाला है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस मेले को राष्ट्रीय सम्मान मिला है

मुख्यमंत्री श्री मोढवाडिया ने कहा कि मुख्यमंत्री के समक्ष जब भी विकास की बात लेकर जाओ, तो वे सवाया देते हैं। श्री मोढवाडिया ने कहा कि राज्य सरकार की विकास कार्यों के प्रति कटिबद्धता व्यक्त की।

वन एवं पर्यावरण मंत्री ने केन्द्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया के प्रयासों से जिले में जारी विभिन्न विकास कार्यों तथा राज्य सरकार की घेड की विकास परियोजना की रूपरेखा भी दी।

उन्होंने जोड़ा कि बरडा तथा घेड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों के आंतरिक सड़क मार्गों के नवीनीकरण के लिए भी करोड़ों रुपए की प्रशासनिक मंजूरी दे दी गई है, जो आगामी समय में जिले की कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार लाएगी। वन विभाग द्वारा 20 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले 'सर्वोदय वन' का उल्लेख करते हुए श्री मोढवाडिया ने कहा कि यह परियोजना पोरबंदर को पर्यावरण एवं पर्यटन क्षेत्र में नई पहचान दिलाएगी। उन्होंने नागरिकों को आश्वासन दिया कि सभी विकास कार्यों के गुणवत्तायुक्त होने के प्रति सरकार सतर्क है और हम पोरबंदर को एक मॉडल जिला बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

पूर्व केबिनेट मंत्री श्री बाबूभाई बोखीरिया ने कहा कि वर्ष 2001 से तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुई विकास की प्रक्रिया राज्य सहित आज पोरबंदर में भव्य परिणाम ला रही है। श्री बोखीरिया ने मेडिकल कॉलेज, कृषि विश्वविद्यालय तथा काऊ सेंचुरी जैसी बड़ी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 किलोमीटर से अधिक के सड़क मार्गों का जाल बिछाया गया है और शहर में पानी की समस्या के स्थायी निवारण के लिए पाइपलाइन सहित ढाँचागत विकास कार्य प्रगति पर हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि पोरबंदर अब महानगर पालिका बना है, तब आगामी कुछ वर्षों में शहर का कलेवर बदल जाएगा और वह सोमनाथ-द्वारका के बीच पर्यटन तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में नई ऊँचाइयाँ पार करेगा।

प्रारंभ में जिला कलेक्टर श्री ए. डी. धानाणी ने स्वागत संबोधन में कहा कि पोरबंदर जिला पिछले कई वर्षों से विकास एवं प्रगति के मार्ग पर निरंतर दौड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन के कामकाज का विवरण देते हुए कहा कि नगर पालिका, योजना विभाग तथा जिला खनिज कोष (डीएमएफ) जैसी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनुदान प्राप्त कर लोगों की सुख-सुविधा के लिए अस्पतालों, विद्यालयों, आँगनबाड़ियों और सड़क-मार्गों जैसे बुनियादी कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। कलेक्टर ने जोड़ा कि सोमनाथ तथा द्वारका के बीच स्थित पोरबंदर को पर्यटन, उद्योग एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे सभी क्षेत्रों में अग्रसर रखने की दिशा में सरकार एवं प्रशासन कटिबद्ध है।

उन्होंने नागरिकों के लिए काम करने के प्रति निरंतर कटिबद्ध रहने के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री अर्जनभाई मोढवाडिया सहित अग्रणियों व सरकार का आभार व्यक्त किया।

समारोह में जिला विकास अधिकारी श्री बी. बी. चौधरी, महानगर पालिका आयुक्त श्री हसमुख प्रजापति, अपर निवासी कलेक्टर श्री रेखाबा सरवैया, वन उप संरक्षक (डीसीएफ) श्री अरुण कुमार व चिराग चांदगुडे, जिला भाजपा प्रभारी डॉ. विमल कथगरा, जिला भाजपा अध्यक्ष श्री चेतनाबेन तिवारी, महासचिव सर्वश्री प्रवीणभाई खोरवा, प्रवीणभाई ओडेदरा, राजेशभाई करगठिया, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री रमेशभाई पटेल, शहर भाजपा अध्यक्ष श्री सागरभाई मोदी, महानुभाव तथा बड़ी संख्या में शहर-जिले के नागरिक उपस्थित रहे।

GCCI और पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के साथ ओपन हाउस सत्र आयोजित

उद्योग, व्यापार और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के हितधारकों ने लिया सक्रिय भाग

गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (GCCI) द्वारा पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के साथ एक महत्वपूर्ण ओपन हाउस सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र में उद्योग, व्यापार एवं लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के प्रमुख हितधारकों ने भाग लेते हुए माल परिवहन, यात्री कनेक्टिविटी तथा लॉजिस्टिक्स दक्षता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता, अहमदाबाद मंडल, पश्चिम रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक वेद प्रकाश ने GCCI की इस पहल की सराहना की। उन्होंने रेलवे की नीतियों, माल परिवहन कार्यक्रमों एवं अवसंरचना विकास से जुड़ी नवीनतम जानकारियाँ साझा कीं।

उन्होंने अपने प्रस्तुतीकरण में बताया कि किस प्रकार भारतीय रेलवे को विश्वस्तरीय सुविधाओं के साथ विकसित किया जा रहा है। गुजरात में रेलवे बजट में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा वंदे भारत एक्सप्रेस और मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना जैसे प्रोजेक्ट राज्य के विकास में नए आयाम स्थापित कर रहे हैं।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए GCCI के अध्यक्ष संदीप इंजीनियर ने भारत को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में रेलवे की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने औद्योगिक विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। इस अवसर पर GCCI के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश गांधी, उपाध्यक्ष अपूर्व शाह एवं कोषाध्यक्ष गौरांग भगत भी उपस्थित रहे।

GCCI लॉजिस्टिक्स टास्कफोर्स के चेयरमैन हितेन वसंत ने लॉजिस्टिक्स प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने में रेलवे की भूमिका को रेखांकित करते हुए वैगन उपलब्धता, अवसंरचना विकास एवं डिजिटल एकीकरण जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई। सत्र में रेलवे अधिकारियों की उपस्थिति वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अन्नू त्यागी, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक डॉ. जेनिया गुप्ता तथा वरिष्ठ मंडल यांत्रिक अभियंता (समन्वय) जगदंबा प्रसाद भी उपस्थित रहे।

ओपन फोरम के दौरान माल परिवहन, पोर्ट कनेक्टिविटी एवं यात्री सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय चर्चा हुई, जिससे उद्योग और रेलवे के बीच सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता सामने आई।

बढ़ते निर्यात एवं लॉजिस्टिक्स डिमांड को देखते हुए समयबद्ध और विश्वसनीय रेल कनेक्टिविटी अत्यंत आवश्यक है, जिसे GCCI और रेलवे के बीच सतत संवाद एवं समन्वय के माध्यम से और बेहतर बनाया जा सकता है।

मंडल रेल प्रबंधक ने व्यापारियों एवं उद्यमियों से प्राप्त सुझावों और समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए तथा आश्वासन दिया कि सभी वाजिब मुद्दों का शीघ्र समाधान किया जाएगा।

आरएलडीए, अहमदाबाद इकाई द्वारा यूनेस्को प्रतिनिधिमंडल का स्वागत

अहमदाबाद स्टेशन पुनर्विकास कार्य का निरीक्षण

रेल भूमि विकास प्राधिकरण (RLDA), अहमदाबाद इकाई द्वारा आज यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र के प्रतिनिधि श्री रोनाल्ड लिन, आईकोमोस विशेषज्ञ सुश्री एलिज़ाबेथ वाइन्स तथा श्री मदन सिंह चौहान का उनके रिएक्टिव मॉनिटरिंग मिशन के अंतर्गत स्वागत किया गया।

प्रतिनिधिमंडल ने अहमदाबाद रेलवे स्टेशन (कालूपुर) पर चल रहे पुनर्विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें परियोजना के उस दृष्टिकोण से अवगत कराया गया, जिसके अंतर्गत आधुनिक यात्री सुविधाओं के साथ-साथ शहर की समृद्ध सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत का समन्वित संरक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है।

भ्रमण के दौरान विशेष रूप से यह प्रस्तुति दी गई कि किस प्रकार परियोजना में केंद्रीय संरक्षित स्मारकों — ब्रिक मीनार एवं झूलता मीनार — को संवेदनशील रूप से शामिल किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य इन ऐतिहासिक धरोहरों को, जो अब तक अपेक्षाकृत कम ध्यान में रही हैं, प्रमुखता प्रदान करते हुए उन्हें शहरी अनुभव का अभिन्न एवं आकर्षक हिस्सा बनाना है।

प्रतिनिधिमंडल ने परियोजना की समावेशी एवं धरोहर-केंद्रित योजना की सराहना की। दोनों विशेषज्ञ ब्रिक मीनार एवं झूटा मीनार की विशिष्ट वास्तुकला से विशेष रूप से प्रभावित हुए तथा इस परियोजना को विरासत-संवेदनशील अवसंरचना विकास के क्षेत्र में एक आदर्श उदाहरण बनने की क्षमता वाला बताया।

युवाओं के लिए केन्द्र सरकार के 'वीबी-जी राम जी यूथ डिजिटल कैम्पेन' में भाग लेकर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का स्वर्णिम अवसर

- लोगो डिजाइन प्रतियोगिता के विजेता को 50 हजार रुपए का आकर्षक पुरस्कार तथा डिजिटल प्रमाणपत्र
- 'My Bharat' पोर्टल के माध्यम से युवा गाँव की प्रगति की गाथा देश के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे

गांधीनगर : केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा देश के ग्रामीण युवाओं की शक्ति तथा सृजनात्मकता को वेग देने के लिए 'My Bharat' पोर्टल के सहयोग से राष्ट्रव्यापी 'वीबी-जी राम जी यूथ डिजिटल कैम्पेन' की घोषणा की गई है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन तथा स्थानीय आजीविका के प्रयासों में युवाओं को डिजिटल माध्यम से जोड़कर राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनाना है।

इस अभियान के द्वारा युवा अपने गाँव के विकास कार्यों, नवीन प्रयोगों तथा बुनियादी स्तर पर आने वाले सकारात्मक परिवर्तनों को वीडियो व डिजाइन के माध्यम से प्रस्तुत कर सकेंगे। 15 से 29 वर्ष आयु समूह के सभी उत्साही युवा 20 मार्च, 2026 तक 'My Bharat' अथवा 'MyGov' पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण करा सकेंगे।

अभियान अंतर्गत आयोजित प्रमुख प्रतियोगिताएँ

वीडियो चैलेंज (रील प्रतियोगिता)

गाँव में हुए विकास कार्यों अथवा आजीविका से संबंधी 30 से 60 सेकेंड का प्रभावशाली शॉर्ट वीडियो बनाकर 'My Bharat' पोर्टल पर अपलोड करना होगा। फाइल साइज अधिकतम् 25 एमबी होना अनिवार्य है।

ऑनलाइन क्विज

'विकसित भारत – जी राम जी एक्ट 2025' तथा सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित 20 प्रश्नों के उत्तर देकर युवा आकर्षक डिजिटल प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं।

लोगो डिजाइन प्रतियोगिता

इस योजना के उद्देश्यों को सार्थक करने वाले श्रेष्ठ लोगो को बनाने वाले युवा विजेता को 50 हजार रुपए का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

यह अभियान केवल युवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म ही नहीं प्रदान करेगा, बल्कि ग्रामीण भारत की प्रगति को नई पहचान देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अधिक जानकारी के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसी की मनरेगा शाखा से संपर्क करने को कहा गया है।

"ऑपरेशन डिग्निटी"

अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से 30 असहाय शहरी बेघरों का रेस्क्यू

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल द्वारा यात्रियों की सुरक्षा, स्वच्छता एवं मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए दिनांक 18 मार्च, 2026 को अहमदाबाद रेलवे स्टेशन परिसर में "ऑपरेशन डिग्निटी" केअंतर्गत विशेष अभियान चलाया गया।

इस अभियान का संचालन रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के स्टाफ तथाअहमदाबाद नगर निगम द्वारा संचालित शहरी बेघरों के आश्रय (Shelter for Urban Homeless) के कर्मियों के संयुक्त सहयोग से किया गया।

अभियान के दौरान स्टेशन परिसर से कुल 30 असहाय शहरी बेघरोंको चिन्हित कर सुरक्षित रूप से रेस्क्यू किया गया। सभी व्यक्तियों कोआवश्यक समन्वय के साथ अहमदाबाद नगर निगम के शहरी बेघरों केआश्रय स्थल (SUH) में आश्रय एवं देखभाल हेतु स्थानांतरित किया गया।

यह पहल रेलवे परिसर में व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ समाजके कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का परिचायक है।पश्चिम रेलवे का अहमदाबाद मंडल भविष्य में भी ऐसे मानवीय एवंजनहितकारी अभियानों को निरंतर जारी रखेगा।

सोना वायदा 5813 रुपये और चांदी वायदा 15239 रुपये लुढ़का: क्रूड ऑयल वायदा में 37 रुपये की नरमी

मुंबई: देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 267468.12 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 50880.88 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 216585.8 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का मार्च वायदा 36400 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 3903.76 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 35285.43 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 151941 रुपये के भाव पर खूलकर, 152449 रुपये के दिन के उच्च और 146757 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 153025 रुपये के पिछले बंद के सामने 5813 रुपये या 3.8 फीसदी गिरकर 147212 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। गोल्ड-गिनी मार्च वायदा 4775 रुपये या 3.81 फीसदी गिरकर 120410 रुपये प्रति 8 ग्राम के भाव पर पहुंचा। गोल्ड-पेटल मार्च वायदा 612 रुपये या 3.89 फीसदी गिरकर 15107 रुपये प्रति 1 ग्राम के भाव पर पहुंचा। सोना-मिनी अप्रैल वायदा 152220 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 152666 रुपये और नीचे में 146861 रुपये पर पहुंचकर, 5808 रुपये या 3.79 फीसदी गिरकर 147300 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा। गोल्ड-टेन मार्च वायदा प्रति 10 ग्राम 153047 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 153370 रुपये और नीचे में 145004 रुपये पर पहुंचकर, 153886 रुपये के पिछले बंद के सामने 6012 रुपये या 3.91 फीसदी गिरकर 147874 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा।

चांदी के वायदाओं में चांदी मई वायदा 245000 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 245674 रुपये और नीचे में 229234 रुपये पर पहुंचकर, 248194 रुपये के पिछले बंद के सामने 15239 रुपये या 6.14 फीसदी घटकर 232955 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। इनके अलावा चांदी-मिनी अप्रैल वायदा 15584 रुपये या 6.14 फीसदी औंधकर 238113 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि चांदी-माइक्रो अप्रैल वायदा 15647 रुपये या 6.16 फीसदी घटकर 238291 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

- कमोडिटी वायदाओं में 50880.88 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 216585.8 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 35285.43 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 36400 पॉइंट के स्तर पर

मेटल वर्ग में 5103.55 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा मार्च वायदा 44.9 रुपये या 3.89 फीसदी घटकर 1108.1 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि जस्ता मार्च वायदा 4.85 रुपये या 1.54 फीसदी गिरकर 309.15 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। इसके सामने एल्यूमीनियम मार्च वायदा 5.7 रुपये या 1.66 फीसदी औंधकर 337.6 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा मार्च वायदा 35 पैसे या 0.19 फीसदी चढ़कर 187.9 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 10315.80 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल मार्च वायदा 9357 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 9357 रुपये और नीचे में 8802 रुपये पर पहुंचकर, 37 रुपये या 0.41 फीसदी घटकर 8961 रुपये प्रति बैरल के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी मार्च वायदा 45 रुपये या 0.5 फीसदी गिरकर 8965 रुपये प्रति बैरल के भाव पर पहुंचा। इनके अलावा नैचुरल गैस मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 288 रुपये के भाव पर खूलकर, 302 रुपये के दिन के उच्च और 288 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 283.3 रुपये के पिछले बंद के सामने 13.9 रुपये या 4.91 फीसदी की बढ़त के साथ 297.2 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि नैचुरल गैस-मिनी मार्च वायदा 13.7 रुपये या 4.83 फीसदी की बढ़त के साथ 297.1 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर कारोबार कर रहा था।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 964 रुपये के भाव पर खूलकर, 2.4 रुपये या 0.25 फीसदी की मजबूती के साथ 970 रुपये प्रति किलो बोला गया।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 23636.83 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 11648.59 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 3962.35 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 699.80 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 16.39 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 417.48 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 7591.12 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 2701.85 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 3.80 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। जबकि कॉटन केंडी के वायदाओं में 2.06 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 10941 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 62944 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 32345 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 456398 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 67137 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 7868 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 21267 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 83665 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 26512 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 25222 लोट के स्तर पर था। इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स मार्च वायदा 37301 पॉइंट पर खूलकर, 37301 के उच्च और 36400 के नीचले स्तर को छूकर, 1117 पॉइंट घटकर 36400 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल अप्रैल 9000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 32.7 रुपये की बढ़त के साथ 1042.1 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस मार्च 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 6.6 रुपये की बढ़त के साथ 12.35 रुपये हुआ।

सोना मार्च 155000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 895.5 रुपये की गिरावट के साथ 342 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मार्च 250000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 4915 रुपये की गिरावट के साथ 2636.5 रुपये हुआ। तांबा मार्च 1150 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 12.3 रुपये की गिरावट के साथ 5.26 रुपये हुआ। जस्ता मार्च 320 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 71 पैसे की नरमी के साथ 0.88 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल अप्रैल 9000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 5.6 रुपये की बढ़त के साथ 1032.1 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस मार्च 280 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 3.25 रुपये की गिरावट के साथ 5.7 रुपये हुआ।

सोना मार्च 140000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 456.5 रुपये की बढ़त के साथ 638.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मार्च 200000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 810 रुपये की बढ़त के साथ 1220.5 रुपये हुआ। तांबा मार्च 1100 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 13.66 रुपये की बढ़त के साथ 16.4 रुपये हुआ। जस्ता मार्च 305 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 64 पैसे के सुधार के साथ 1 रुपये हुआ।

वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे (20 मार्च): गुजरात का GDCH, अहमदाबाद बन रहा ओरल कैंसर के खिलाफ 'रक्षा-कवच', प्रिवेंटिव केयर से हजारों को मिल रहा जीवनदान

▸▸ वर्ष 2025 में 12,915 स्क्रीनिंग में 3,023 प्री-कैंसर केस की पहचान, समय रहते हजारों लोगों को कैंसर से बचाया गया

▸▸ 33 जिलों में 282 डेंटिस्ट्स का मिशन मोड अभियान, राज्यव्यापी स्क्रीनिंग और जागरूकता का मजबूत नेटवर्क

▸▸ वर्ष 2025 में GDCH अहमदाबाद में 2.24 लाख से अधिक मरीजों ने ली डेंटल OPD सेवाएँ

▸▸ मोबाइल डेंटल टीम और 45 विशेष डेंटल आउटरीच कैंपों की मदद से जेल कैदियों, गर्भवती महिलाओं और विशेष बच्चों सहित 4,980+ लाभार्थियों तक ओरल हेल्थ जाँच सेवाएँ पहुँचाई गईं

गांधीनगर, 19 मार्च : गुजरात का गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (GDCH), अहमदाबाद आज न केवल गुजरात बल्कि पड़ोसी राज्यों के लिए भी मुख स्वास्थ्य और ओरल कैंसर की रोकथाम का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के दूरदर्शी नेतृत्व में इस संस्था ने ओरल कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के खिलाफ एक मजबूत ढाल तैयार की है। गुजरात सरकार की 'प्रिवेंटिव हेल्थकेयर' नीति का ही परिणाम है कि आज कैंसर को उसके पनपने से पहले ही (Pre-Malignant स्टेज पर) पहचानने में बड़ी सफलता मिल रही है। यह प्रयास न केवल जीवन बचा रहा है, बल्कि स्वास्थ्य तंत्र पर पड़ने वाले दबाव को भी प्रभावी रूप से कम कर रहा है।

वर्ष 2025 में GDCH संस्थान की विशेष पहल से हुई 3,023 प्री-कैंसर केस की पहचान

वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे 2026 के अवसर पर जारी आंकड़ों के अनुसार, GDCH अहमदाबाद ने वर्ष 2025 में ओरल कैंसर की पूर्व अवस्था यानी Pre-Malignant Diseases (PMDs) के 3,023 मामलों की पहचान की, जो वर्ष 2024 के 2,617 मामलों की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाती है। शुरुआती स्तर पर इन रोगों की पहचान ने न केवल हजारों परिवारों को कैंसर के खौफ से बचाया है, बल्कि राज्य के कैंसर संस्थानों पर पड़ने वाले सर्जिकल बोझ को भी कम किया है।

स्क्रीनिंग और जागरूकता: 33 जिलों में 282 डेंटिस्ट्स का 'मिशन मोड' अभियान

मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल के मार्गदर्शन में, राज्य की NOHP (नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम) टीम और GDCH अहमदाबाद ने 'वर्ल्ड ओरल डे मन्थ' (20 मार्च से 20 अप्रैल 2025) के दौरान एक व्यापक अभियान चलाया था। इस दौरान राज्य के 33 जिलों में 282 डेंटिस्ट्स द्वारा 12,915 लोगों की सघन स्क्रीनिंग की गई। इस अभियान के दौरान 265 हेल्थ टॉक्स आयोजित किए गए, 2 वॉकथॉन निकाली गईं और 94 स्थानों पर 'तंबाकू निषेध' की शपथ दिलाई गई। साथ ही, ग्रामीण स्तर पर मुख स्वास्थ्य की निगरानी को मजबूत करने के लिए आशा (ASHA) कार्यकर्ताओं को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिससे कैंसर की पहचान जमीनी स्तर तक संभव हो सकी।

इसी कड़ी में, GDCH संस्थान की नियमित ओपीडी सेवाओं ने भी मुख स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता को स्पष्ट रूप से दर्शाया है। जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 के दौरान कुल 2,24,130+ मरीजों ने डेंटल ओपीडी सेवाओं का लाभ लिया। वहीं वर्ष 2026 में भी यह रुझान निरंतर बना हुआ है, जहाँ जनवरी माह में 17,788 और फरवरी माह में 17,564 मरीजों ने उपचार प्राप्त किया। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि राज्य में लोग अब समय रहते ओरल हेल्थ के प्रति जांच और उपचार के प्रति अधिक सजग हो रहे हैं।

GDCH की 'आउटरीच' पहल: स्कूल से लेकर जेल तक पहुँच रहा अत्याधुनिक उपचार

गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (GDCH), अहमदाबाद ने अपने नियमित चिकित्सकीय कार्यों से आगे बढ़कर समाज के वंचित और दूरस्थ वर्गों तक स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाने का सराहनीय कार्य किया है। इस पहल के अंतर्गत मोबाइल डेंटल टीम और 45 विशेष डेंटल कैंपों के माध्यम से जेल कैदियों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और विशेष बच्चों सहित 4,980+ लाभार्थियों तक ओरल हेल्थ जाँच सेवाएँ सफलतापूर्वक पहुँचाई गईं। इस पहल की विशेषता यह रही कि एक ओर जहाँ जेल कैदियों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों जैसे संवेदनशील वर्गों के लिए पृथक स्क्रीनिंग और उपचार की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई, वहीं दूसरी ओर स्कूलों में आयोजित डेंटल कैंपों में विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों को प्राथमिकता के साथ उपचार उपलब्ध कराया गया। बच्चों के दंत स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए 'पिट एंड फिशर सीलेंट' और 'फ्लोराइड वार्निश' जैसे आधुनिक प्रिवेंटिव उपचार स्कूल परिसरों में ही प्रदान किए गए, ताकि प्रारंभिक अवस्था में ही दाँतों से संबंधित रोगों और अन्य ओरल हेल्थ समस्याओं की प्रभावी रोकथाम की जा सके। वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे के अवसर पर प्रस्तुत GDCH अहमदाबाद के ये प्रयास और उपलब्धियाँ इस बात को रेखांकित करती हैं कि यह संस्थान देश में ओरल हेल्थ केयर के क्षेत्र में एक 'रोल मॉडल' के रूप में तेजी से स्थापित हो रहा है।

गुजरात में गैस संकट पर बहस और आपूर्ति बढ़ने की चिंताओं के बीच अफवाहों से दूर रहने की अपील

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत

अमेरिका और इज़राइल ईरान पर हो रहे हमलों और अत्याचारों के सामने "हमें क्या करना चाहिए" की नीति अपनाकर चुप बैठे रहे। अब वे भी इस युद्ध के दुष्परिणामों का शिकार हो रहे हैं। अगर आप अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाते, तो दुनिया की मौजूदा स्थिति इस बात का जीता-जागता उदाहरण है कि अन्याय की आग आपको भी जला देती है।

इस बीच, ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकाबंदी से दुनिया भर के कई देशों को तेल की आपूर्ति बाधित हो गई है। भारत में तेल और गैस का जो संकट चल रहा है, वह कई मायनों में चिंताजनक है। हालांकि सरकार का कहना है कि देश के पास पर्याप्त रणनीतिक और वाणिज्यिक भंडार हैं। घरों और वाहनों के लिए आपूर्ति में कोई कमी नहीं आई है। सरकार ने उपभोक्ताओं से शांति बनाए रखने और अनावश्यक जमाखोरी से बचने की अपील की है। लेकिन समस्या यह है कि जहां सरकार ईंधन आपूर्ति को पूरी तरह से सामान्य और सुरक्षित बता रही है, वहीं देश के कई हिस्सों से खाना पकाने की गैस को लेकर दहशत की खबरें आ रही हैं।

सवाल यह है कि जब सरकार आश्वासन दे रही है कि सब ठीक है और जमाखोरी न करने की सलाह दे रही है, तो खाना पकाने की गैस की कमी का डर लोगों में कैसे फैल गया? और वास्तव में कमी क्यों है? दरअसल, जब ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को अवरुद्ध कर दिया, जिससे तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित हुई, तो सरकार ने तुरंत खाना पकाने की गैस सिलेंडरों की कीमत बढ़ा दी। इसके साथ ही, 25 दिनों के बाद नया सिलेंडर मिलने की शर्त भी लगा दी गई। शायद इसी वजह से लोगों को लगा कि खाना पकाने की गैस की कमी का असर जल्द ही दिखने वाला है। फिलहाल, आपूर्ति विभाग खाना पकाने की गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए हर जगह छापेमारी कर रहा है, वहीं खाना पकाने की गैस के सिलेंडरों के साथ-साथ व्यावसायिक सिलेंडरों की कमी के कारण कई रेस्तरां बंद होने की कगार पर हैं। और इस पर निर्भर रहने वाले डिलीवरीकर्मियों की हालत भी दयनीय हो गई है।

इसलिए, राष्ट्र के हित में हम सभी के लिए यह वांछनीय है कि हम एक साथ आएं, अफवाहों से दूर रहें और लोगों के बीच फैल रही दहशत का हिस्सा न बनें।

एलपीजी, एलएनजी, पीएनजी, सीएनजी क्या हैं? इनके उपयोग, अंतर और सुरक्षा संबंधी जानकारी देने वाली गाइड

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत।

हमने कई गैसों के नाम तो सुने हैं, लेकिन उनके तकनीकी स्वरूप और उपयोग के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। इन सभी गैसों के मूल में गैस शब्द है, और फिर भी इन सभी का स्वरूप और उपयोग अलग-अलग होता है। आइए, इनके स्वरूप और उपयोग को जानें।

एलपीजी का अर्थ है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस:-

यह एलपीजी प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। प्रोपेन और ब्यूटेन को दबाव में भरकर तरल रूप में सिलेंडर में भरा जाता है। यह गैस भारी होती है, इसलिए रिसाव होने पर आसपास के वातावरण को काफी नुकसान पहुंचाती है। हमारे देश में एलपीजी का उपयोग मुख्य रूप से खाना पकाने के लिए किया जाता है। साथ ही, इसका उपयोग कुछ उद्योगों में भी होता है।नवसर्जन संस्कृत 4 1

एलएनजी का अर्थ है द्रवीकृत प्राकृतिक गैस:

यह प्राकृतिक गैस है। इसमें मुख्य रूप से मीथेन होती है। मीथेन को -162 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करके द्रव रूप में परिवर्तित किया जाता है, जिससे इसका आयतन 600 गुना कम हो जाता है और इसे जहाजों द्वारा लंबी दूरी तक ले जाया जा सकता है। एलएनजी का उपयोग मुख्य

रूप से बिजली संयंत्रों और इस्पात उद्योगों में होता है, लेकिन इसका उपयोग उर्वरक बनाने में भी किया जाता है। हम एलएनजी के लिए कतर (एक खाड़ी देश) पर भी निर्भर हैं।नवसर्जन संस्कृत 1 4

पीएनजी का अर्थ है पाइपयुक्त प्राकृतिक गैस:-

यह शुद्ध प्राकृतिक गैस है जो पाइपलाइन के माध्यम से सीधे घरों तक पहुंचाई जाती है। चूंकि यह गैस वजन में बहुत हल्की होती है, इसलिए रिसाव के बाद जमीन पर रहने के बजाय ऊपर की ओर उठती है। परिणामस्वरूप, इसका सेवन एलपीजी की तुलना में अधिक सुरक्षित है। भारत सरकार गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए शहरों में पीएनजी नेटवर्क का तेजी से विस्तार कर रही है। पीएनजी वास्तव में द्रवीकृत प्राकृतिक गैस का गैसीय रूप है। इसका अर्थ यह है कि इस गैस के लिए भी हम कतर (खाड़ी देशों) पर निर्भर हैं।नवसर्जन संस्कृत 3 1

सीएनजी का अर्थ है संपीड़ित प्राकृतिक गैस: –

जब प्राकृतिक गैस को बहुत अधिक दबाव पर संपीड़ित किया जाता है, तो वह सीएनजी बन जाती है। सीएनजी का उपयोग वाहनों में पेट्रोल और डीजल के विकल्प के रूप में किया जाता है। इससे प्रदूषण कम होता है और यह पेट्रोल और डीजल से सस्ता भी है। सीएनजी की बात करें तो, हम 50% आयात पर निर्भर हैं, जबकि इतनी ही मात्रा में उत्पादन हम देश में ही करते हैं। यह विभिन्न गैसों की अद्भुत दुनिया है।

सूरत में शक बना कातिल: लव मैरिज का दर्दनाक अंत, पति ने पत्नी की सरेआम चाकू मारकर की हत्या

गुजरात के Surat शहर के Rander इलाके में एक सनसनीखेज हत्या की वारदात ने पूरे क्षेत्र में दहशत और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है। एक महिला की दिनदहाड़े सरेआम हत्या कर दी गई, और जांच में सामने आया कि इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाला कोई और नहीं, बल्कि उसका अपना पति ही था। यह घटना न केवल एक आपराधिक मामला है, बल्कि यह रिश्तों में बढ़ते अविश्वास और घरेलू तनाव की भयावह परिणति को भी उजागर करती है।

मृतका की पहचान पूजा के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बिहार की रहने वाली थी और सूरत में केटरिंग का काम करती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात सरफराज नाम के युवक से हुई थी, जो खुद भी बिहार का ही निवासी था। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और उन्होंने प्रेम विवाह कर लिया। पिछले करीब दो वर्षों से दोनों सूरत में साथ रह रहे थे, लेकिन समय के साथ उनके रिश्ते में खटास आने लगी। आए दिन होने वाले झगड़े और आपसी विवाद ने उनके वैवाहिक जीवन को तनावपूर्ण बना दिया था।

पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि सरफराज को अपनी पत्नी पर किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध होने का शक था। इसी शक ने धीरे-धीरे उसके मन में गुस्सा और असुरक्षा की भावना को जन्म दिया, जो अंततः एक खतरनाक रूप में सामने आई। घटना वाले दिन भी पति-पत्नी के बीच तीखा विवाद हुआ था। झगड़े के बाद पूजा अपने एक परिचित नरेश के कमरे में चली गई, जिससे सरफराज का शक और बढ़ गया।

गुस्से में आगबबूला सरफराज पत्नी की तलाश में नरेश के कमरे तक पहुंच गया। वहां उसने पूजा को नरेश के साथ देखा, जिसके बाद स्थिति और बिगड़ गई। दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई, जो कुछ ही पलों में हिंसा में बदल गई। गुस्से में अपना आपा खोते हुए सरफराज ने तेज धार वाले चाकू से पूजा की छाती पर कई वार कर दिए। हमला इतना अचानक और बेरहमी से किया गया कि मौके पर मौजूद लोग कुछ समझ ही नहीं पाए और वहां अफरा-तफरी मच गई।

घटना के बाद गंभीर रूप से घायल पूजा को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस खबर के फैलते ही इलाके में सनसनी फैल गई और लोग स्तब्ध रह गए कि एक पति अपनी ही पत्नी के साथ इतनी क्रूरता कैसे कर सकता है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति सरफराज को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और बताया कि पत्नी के कथित संबंधों के शक ने उसे इस हद तक पहुंचा दिया। पुलिस का कहना है कि यह हत्या पूर्वनियोजित नहीं थी, बल्कि अचानक गुस्से और आवेग में की गई वारदात है, हालांकि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है।

यह घटना एक बार फिर यह सवाल खड़ा करती है कि रिश्तों में बढ़ता अविश्वास और संवाद की कमी किस तरह हिंसक रूप ले सकती है। समाज में ऐसे कई मामले सामने आते हैं, जहां शक और गुस्सा मिलकर परिवारों को तबाह कर देते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे हालात में परामर्श और संवाद बेहद जरूरी होता है, ताकि विवाद को समय रहते सुलझाया जा सके।

फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है और अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है। इलाके में इस घटना को लेकर लोगों में डर और गुस्सा दोनों है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं समाज के लिए गंभीर चेतावनी हैं, जहां रिश्तों की नींव कमजोर होती जा रही है।

यह दर्दनाक वारदात न केवल एक परिवार को उजाड़ गई, बल्कि यह भी याद दिलाती है कि क्रोध और संदेह के क्षणिक आवेग किस तरह जीवन भर का पछतावा बन सकते हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि कानून इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और क्या इससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस संदेश जा पाएगा।

अफवाहों के साए से बाहर आया वडोदरा, प्रशासन की सख्ती और जागरूकता से लौटा भरोसा

गुजरात के Vadodara शहर ने बीते कुछ दिनों में एक ऐसी स्थिति का सामना किया, जिसने यह दिखा दिया कि आज के डिजिटल युग में अफवाहें कितनी तेजी से वास्तविकता का रूप ले सकती हैं। मिडिल ईस्ट में चल रहे हालात को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ भ्रामक वीडियो और संदेश वायरल हुए, जिनमें रसोई गैस की भारी कमी का दावा किया गया। इन संदेशों ने देखते ही देखते लोगों के मन में डर और असुरक्षा की भावना पैदा कर दी। परिणामस्वरूप शहर के कई हिस्सों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लग गईं और लोग जरूरत से अधिक सिलेंडर बुक करने लगे, जिससे एक कृत्रिम संकट जैसी स्थिति बन गई। शुरुआती घंटों में हालात इतने बिगड़ गए कि सामान्य आपूर्ति व्यवस्था पर अचानक दबाव बढ़ गया। कई उपभोक्ताओं ने एहतियात के नाम पर अतिरिक्त सिलेंडर जमा कर लिए, जबकि कुछ एजेंटों ने इस स्थिति का फायदा उठाकर अवैध वसूली शुरू कर दी। इससे न केवल आम नागरिकों में असंतोष बढ़ा, बल्कि वास्तविक जरूरतमंद लोगों को गैस प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम ने प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी,

क्योंकि यह संकट वास्तविक कमी का नहीं, बल्कि अफवाहों से पैदा हुई घबराहट का परिणाम था।

स्थिति की गंभीरता को समझते हुए जिला प्रशासन ने तुरंत सक्रियता दिखाई और बहुस्तरीय रणनीति के साथ मैदान में उतरा। सबसे पहले उन स्थानों की पहचान की गई, जहां पैनिक बुकिंग और अनावश्यक भंडारण अधिक हो रहा था। इसके बाद अनधिकृत रूप से जमा किए गए गैस सिलेंडरों की जब्ती की कार्रवाई शुरू की गई। साथ ही, ऐसे एजेंटों और बिचौलियों पर सख्त कार्रवाई की गई, जो लोगों के डर का फायदा उठाकर अतिरिक्त पैसे वसूल रहे थे। प्रशासन का यह कड़ा रुख एक स्पष्ट संदेश था कि किसी भी तरह की कालाबाजारी या अफवाह फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

इसके साथ ही प्रशासन ने यह भी समझा कि केवल सख्ती से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि लोगों के बीच भरोसा कायम करना भी उतना ही जरूरी है। इसी उद्देश्य से अधिकारियों ने नियमित रूप से गैस एजेंसियों और वितरण केंद्रों का दौरा करना शुरू किया। हर स्तर पर निगरानी रखी गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपूर्ति में कोई बाधा न आए और सभी उपभोक्ताओं को समय पर गैस मिल सके। इसके अलावा, एक विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, जिसके माध्यम से नागरिक सीधे प्रशासन से संपर्क कर सकते थे और गैस स्टॉक तथा आपूर्ति की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते थे। प्रशासन की इस पारदर्शी और सक्रिय पहल का असर धीरे-धीरे दिखाई देने लगा। जहां पहले लोग अफवाहों के कारण घबराकर अनावश्यक बुकिंग कर रहे थे, वहीं अब वे वास्तविक जानकारी मिलने के बाद संयम बरतने लगे। गुरुवार को हेल्पलाइन पर मात्र 62 कॉल दर्ज होना इस बात का प्रमाण है कि लोगों में भरोसा लौट रहा है और वे अब बिना वजह घबराने के बजाय स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पैनिक बुकिंग में आई भारी कमी ने भी वितरण प्रणाली को फिर से संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इस पूरे घटनाक्रम में समाज के जागरूक नागरिकों की भूमिका भी उल्लेखनीय रही। भताड़ी जंपा रोड स्थित एक गैस एजेंसी पर पहुंचे भूपेंद्रभाई शंभूलाल शाह जैसे नागरिकों ने न केवल खुद अतिरिक्त सिलेंडर जमा कराया, बल्कि दूसरों से भी ऐसा करने की अपील की। उनका यह कदम इस बात का प्रतीक है कि जब समाज और प्रशासन साथ मिलकर काम करते हैं, तो किसी भी संकट का समाधान संभव हो जाता है। इसी तरह, गैस एजेंसियों के प्रबंधकों ने भी लगातार यह स्पष्ट किया कि गैस की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति पूरी तरह नियमित है। आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है। 19 मार्च 2026 तक वडोदरा जिले में कुल 19,722 गैस सिलेंडरों का स्टॉक उपलब्ध है। इसमें Indian Oil Corporation के पास 9,996, Bharat Petroleum के पास 3,788 और Hindustan Petroleum के पास 5,941 सिलेंडर मौजूद हैं। जिले की दैनिक खपत लगभग 14,098 सिलेंडर है, जिससे यह साफ होता है कि उपलब्ध स्टॉक मांग से अधिक है और किसी भी प्रकार की कमी की आशंका नहीं है।

यह पूरा मामला एक महत्वपूर्ण सबक भी देता है कि सूचना के इस युग में किसी भी खबर को बिना सत्यापन के स्वीकार करना कितना खतरनाक हो सकता है। सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहें न केवल व्यक्तिगत स्तर पर डर पैदा करती हैं, बल्कि सामूहिक रूप से एक बड़ी समस्या का रूप ले सकती हैं। ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी के साथ-साथ नागरिकों की जागरूकता भी उतनी ही जरूरी है।

आज वडोदरा में हालात पूरी तरह सामान्य हो चुके हैं। गैस एजेंसियों के बाहर लगी लंबी कतारें अब खत्म हो गई हैं, आपूर्ति सुचारू रूप से चल रही है और लोगों के चेहरों पर फिर से विश्वास दिखाई दे रहा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें और किसी भी प्रकार की अफवाहों से दूर रहें। यह घटना इस बात का उदाहरण है कि संकट चाहे वास्तविक हो या कृत्रिम, यदि समय पर सही कदम उठाए जाएं और समाज सहयोग करे, तो हर चुनौती का समाधान संभव है।

एआई से छप रहे थे जाली नोट: सूरत में हाई-टेक करेंसी फैक्ट्री का भंडाफोड़, करोड़ों की नकली रकम बरामद

गुजरात के Surat और Ahmedabad से सामने आया नकली करेंसी रैकेट अब एक साधारण आपराधिक घटना नहीं, बल्कि तकनीक के खतरनाक दुरुपयोग का बड़ा उदाहरण बनकर उभरा है। इस पूरे मामले में जिस तरह आधुनिक तकनीक, विदेशी संसाधनों और संगठित नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया, उसने जांच एजेंसियों को भी चौंका दिया है। Ahmedabad Crime Branch द्वारा की गई कार्रवाई में 2.38 करोड़ की जाली करेंसी जब्त की गई है, लेकिन इस केस की असली गंभीरता उस तकनीकी चालाकी में छिपी है, जिसके जरिए यह पूरा गिरोह लंबे समय से सक्रिय था।

जांच में सामने आया है कि इस रैकेट का मास्टरमाइंड मुकेशभाई लाखाभाई थुम्मर था, जिसने सूरत स्थित अपने घर को एक हाई-टेक सीक्रेट प्रिंटिंग यूनिट में बदल दिया था। बाहर से सामान्य दिखने वाले इस घर के भीतर अत्याधुनिक प्रिंटिंग मशीनें, हाई क्वालिटी पेपर और डिजिटल टूल्स के जरिए नकली नोटों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा रहा था। यह कोई पारंपरिक नकली नोट छापने वाला गिरोह नहीं था, बल्कि पूरी तरह से तकनीक-आधारित, योजनाबद्ध और संगठित आपराधिक नेटवर्क था।

इस पूरे मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि आरोपी केवल सामान्य प्रिंटिंग तकनीकों पर निर्भर नहीं थे, बल्कि उन्होंने Artificial Intelligence आधारित एडवांस्ड फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया। इन सॉफ्टवेयर की मदद से भारतीय करेंसी के डिज़ाइन, रंग, टेक्सचर और सुरक्षा चिह्नों को बेहद बारीकी से कॉपी किया गया। नकली नोटों पर 'RBI' और 'भारत' जैसे निशान भी इतने सटीक तरीके से बनाए गए थे कि आम आदमी के लिए असली और नकली में फर्क करना लगभग नामुमकिन हो गया था। यह इस बात का संकेत है कि अपराध अब पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़कर डिजिटल और तकनीकी स्तर पर भी खतरनाक रूप ले चुका है।

जांच एजेंसियों ने यह भी खुलासा किया

है कि इस गिरोह का विदेशी कनेक्शन भी था। आरोपी Alibaba जैसे अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए सिक्योरिटी थ्रेड वाले विशेष कागज मंगवाते थे। इन कागजों का इस्तेमाल असली नोटों की तरह दिखने वाले नकली नोट तैयार करने में किया जाता था। इस तरह के संसाधनों के उपयोग ने नकली नोटों की गुणवत्ता को इतना उच्च बना दिया था कि वे बाजार में आसानी से चल सकते थे और अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते थे। क्राइम ब्रांच की टीम ने सूरत और अहमदाबाद में एक साथ छापेमारी कर इस पूरे नेटवर्क को बेनकाब किया। कार्रवाई के दौरान 2.38 करोड़ की नकली करेंसी जब्त की गई, जिसमें अहमदाबाद से 2.10 करोड़ और सूरत से 28 लाख शामिल हैं। इसके अलावा, लगभग 25 लाख कीमत की एक कार, सिक्योरिटी पेपर की रीम, अत्याधुनिक प्रिंटर, लैपटॉप, पेपर कटिंग मशीन और नोट गिनने की मशीन भी बरामद की गई है। इन सभी उपकरणों से यह स्पष्ट होता है कि यह गिरोह पूरी तरह से संगठित और पेशेवर तरीके से काम कर रहा था। इस मामले में अब तक कुल सात आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें सूरत के कई स्थानीय नाम शामिल हैं, जो इस नेटवर्क का हिस्सा थे और अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर रहे थे। कटारगाम इलाके से एक महिला आरोपी की गिरफ्तारी भी इस बात की ओर इशारा करती है कि यह गिरोह व्यापक स्तर पर फैला हुआ था और इसमें विभिन्न स्तरों पर लोगों की भागीदारी थी। पुलिस अब इन सभी आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है, ताकि इस नेटवर्क के अन्य लिंक और संभावित सहयोगियों का पता लगाया जा सके।

अधिकारियों का मानना है कि यह रैकेट केवल राज्य या देश तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके तार अंतरराष्ट्रीय स्तर तक जुड़े हो सकते हैं। जिस तरह विदेशी प्लेटफॉर्म से सामग्री मंगाई जा रही थी और उन्नत तकनीक का उपयोग किया जा रहा था, उससे यह आशंका और भी मजबूत हो जाती है कि यह एक बड़े सिंडिकेट का हिस्सा हो सकता है। ऐसे में जांच एजेंसियां अब इस मामले को और गहराई से खंगाल रही हैं, ताकि पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जा सके। यह घटना एक गंभीर चेतावनी भी है कि तकनीक, जो आमतौर पर विकास और सुविधा के लिए उपयोग की जाती है, उसका गलत इस्तेमाल किस तरह समाज और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन सकता है। नकली करेंसी न केवल बाजार में भ्रम पैदा करती है, बल्कि यह देश की आर्थिक स्थिरता को भी प्रभावित कर सकती है। ऐसे में इस तरह के रैकेट का समय रहते पर्दाफाश होना बेहद महत्वपूर्ण है।

फिलहाल, इस कार्रवाई से एक बड़े खतरे को टाल दिया गया है, लेकिन यह मामला यह भी दर्शाता है कि भविष्य में अपराध और भी अधिक तकनीकी और जटिल हो सकते हैं। इसलिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भी लगातार अपने तरीकों और तकनीकों को अपडेट करना होगा, ताकि वे ऐसे हाई-टेक अपराधों का प्रभावी तरीके से मुकाबला कर सकें।

भावनगर मंडल से होकर चलने वाली 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरों का विस्तार

यात्रियों की सुविधा एवं बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे द्वारा भावनगर मंडल से होकर संचालित 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार ट्रेनों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:

1.ट्रेन संख्या 09207 बांद्रा टर्मिनस–भावनगर साप्ताहिक स्पेशल को 27 मार्च, 2026 तक अधिसूचित किया गया था, जिसे अब 31 जुलाई, 2026 तक संचालित किया जाएगा। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09208

भावनगर–बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक स्पेशल को 26 मार्च, 2026 तक अधिसूचित किया गया था, जिसे अब 30 जुलाई 2026 तक संचालित किया जाएगा।

2.ट्रेन संख्या 09211 गांधीग्राम–बोटाद दैनिक स्पेशल एवं 09212 बोटाद–गांधीग्राम दैनिक स्पेशल दोनों को 31 मार्च, 2026 तक अधिसूचित किया गया था, जिसे अब 31 जुलाई, 2026 तक संचालित किया जाएगा।

3.ट्रेन संख्या 09216 भावनगर–गांधीग्राम दैनिक स्पेशल एवं 09215 गांधीग्राम–भावनगर दैनिक स्पेशल दोनों को 31 मार्च, 2026 तक अधिसूचित किया गया था, जिसे अब 31 जुलाई, 2026 तक संचालित किया जाएगा।

4.ट्रेन संख्या 09529 धोला–भावनगर दैनिक स्पेशल एवं 09530 भावनगर–धोला दैनिक स्पेशल दोनों को 31 मार्च, 2026 तक अधिसूचित किया गया था, जिसे अब 31 जुलाई, 2026 तक संचालित किया जाएगा।

5.ट्रेन संख्या 09018 वेरावल–बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक स्पेशल को 30 मार्च, 2026 तक अधिसूचित किया गया था, जिसे अब 27 जुलाई, 2026 तक तथा ट्रेन संख्या 09017 बांद्रा टर्मिनस–वेरावल साप्ताहिक स्पेशल को 29 मार्च, 2026 तक अधिसूचित किया गया था, जिसे अब 26 जुलाई, 2026 तक संचालित किया जाएगा।

यात्रियों से अनुरोध है कि वे यात्रा से पूर्व ट्रेनों के समय, ठहराव एवं संरचना की जानकारी के लिए भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in का अवलोकन करें।

आरक्षित ट्रेनों के लिए टिकटों की बुकिंग 20 मार्च 2026 (शुक्रवार) से यात्री आरक्षण केंद्रों एवं IRCTC की वेबसाइट पर प्रारंभ होगी। यात्रीगण ट्रेनों के समय, ठहराव एवं संरचना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in पर अवलोकन कर सकते हैं।